MR. CHAIRMAN : The question is :

"That the Bill to provide for the repeal of the Tea Districts Emigrant Labour Act, 1932, and for matters connected therewith, be taken into consideration."

The motion was adopted.

MR. CHAIRMAN : Now the House will take up clause-by-clause consideration of the Bill. The question is :

"That clause 2 stand part of the Bill."

The motion was adopted.

Clause 2 was added to the Bill.

Clause 3 was added to the Bill.

Clause 1 (Short title.)

Amendment made :

Page 1, line 4,—

for "1967" *substitute* "1970" (2)

(Shri Bhagwat Jha Azad)

MR. CHAIRMAN : The question is :

"That clause 1, as amended, stand part of the Bill."

The motion was adopted.

Clause 1, as amended, was added to the Bill.

Enacting Formula

Amendment made:

Page 1, line 1,—

for "Eighteenth" *substitute*—

"Twenty-first" (1)

(Shri Bhagwat Jha Azad)

MR. CHAIRMAN : The question is :

"That the Enacting Formula, as amended, stand part of the Bill."

The motion was adopted.

The Enacting Formula, as amended, was added to the Bill.

The Title was added to the Bill.

SHRI BHAGWAT JHA AZAD : Sir, I move :

"That the Bill, as amended, be passed."

MR. CHAIRMAN ; The question is :

"That the Bill, as amended, be passed."

The motion was adopted.

---

17. hrs.

DISCUSSION RE: ECONOMICALLY BACKWARD REGIONS IN THE COUNTRY ESPECIALLY THE EASTERN DISTRICTS OF U. P.

श्री राजदेव सिंह (जौनपुर) : सभापति महोदय, हमारे देश के पिछड़े क्षेत्रों के बारे में आज बहस का जो मौका मिला है, उसके लिये मैं आप को बधाई देता हूं और साथ ही साथ यह कहना चाहता हूं कि इन क्षेत्रों की बड़ी पुरानी कहानी है। आज तक इन क्षेत्रों की तरक्की के लिये कोई काम ऐसा नहीं किया गया, जिससे....

श्री राम सेवक यादव (बाराबंकी) : सभापति महोदय, यह मामला गृह मंत्रालय से सम्बन्धित है या वित्त मंत्रालय से सम्बन्धित या योजना से सम्बन्धित है, क्योंकि यह पिछड़े- पन का प्रश्न है, आर्थिक सवाल है या कहीं पर डण्डा चलाने का सवाल है, क्या गृह मंत्रालय वहां किसी आई० जी० को या किसी दूसरे अफसर को भेजेंगे ....

सभापति महोदय : आप अपना भाषण जारी रखें।

श्री राजदेव सिंह : मैं कह रहा था कि इन क्षेत्रों की तरक्की के लिये आज तक कोई

ऐसा काम नहीं हुआ, जिससे इन क्षेत्रों की उन्नति हो सके ।

श्रीमन्, पूरे हिन्दुस्तान में 289 जिलों में गरिबी है, उन में से 58 जिले बहुत ही पिछड़े हुए हैं, जो समूचे देश में फैले हुए हैं । 1955-56 में नैशनल कान्सिल आफ एप्लाइड इकान मिक रिसर्च ने 289 जिलों का सर्वेक्षण किया था, उन में से 29 जिले इतने ज्यादा पिछड़े हुए मिले, जिनकी आमदानी प्रति व्यक्ति साल में 146 रु० या उस से भी कम थी । उस के बाद जो दूसरा स्लैब उन्होने दिया, उस में भी 29 जिले मिले, जिन की आमदनी प्रति व्यक्ति साल में 147 रु० से 173 रुपये थी । इस तरह से 58 जिले समूचे देश में पाये गये जिनकी आमदनी प्रति व्यक्ति 173 रु० से नीचे पाई गई । अब अगर इन 58 जिलों का ब्रेक-अप आप देखें तो वह इस तरह से है कि 22 जिले तो यू० पी० में हैं, बिहार में 12 हैं, उड़ीसा में 5 हैं, मध्य प्रदेश में 5 हैं, मैसूर में 3 हैं, महाराष्ट्र में 3 हैं, आसाम में 2 हैं, बंगाल में 2 हैं, आन्ध्र में 2 हैं, तामिलनाडु और राजस्थान में एक-एक जिले हैं ।

अब यू० पी० के इन 22 जिलों में से जिन 14 जिलों के बारे में मैंने अपना मोशन दिया है. उन का ब्रेक-अप भी आप के सामने रखना जरुरी है । इन में 4 पहाड़ी जिले हैं, 4 जिले बुन्देल-खण्ड के हैं और 14 जिले ईस्टर्न यू० पी० के हैं, बनारस कमिश्नरी के 5 जिले, गोरखपुर के 4 और फैजाबाद के 5 जिले हैं । अब, सभापति महोदय, इन 58 पिछड़े हुए जिलों की आबादी का जहां तक सम्बन्ध है, वह पूरे देश की आबादी का पांचवा हिस्सा है, देश की इतनी बड़ी आबादी आज भी पिछड़ी हुई है और इस पिछड़ी हुई 40 पर-सेन्ट आबादी में से ईस्टर्न यू० पी० के 22 पिछड़े हुए जिलों में 80 परसेन्ट आबादी है । इन 14 पूर्वी जिलों में 1956-57 के बाद से आज तक विकास का काम बहुत धीमा रहा, उन की हालत आज भी उसी तरह है, जैसी उस समय थी जब उन का सर्वेक्षण किया गया था ।

श्रीमन्, दूसरी बात मैं यह कह देना चाहता हू कि पूर्वी उत्तर प्रदेश के ये 14 जिले आबादी के ख्याल से बहुत ही घने बसे हुए हैं, एक-एक वर्गमिल के अन्दर 1100 आदमी रहते हैं, जब कि यू० पी० की औसत आबादी 400 आदमियों से नीचे है और हिन्दुस्तान की औसत आबादी उस से भी कम है । दूसरे प्रदेशों के मुकाबले यू० पी० की तो शुरू से ही अवहेलना की गई लेकिन इन 14 जिलों की हालत तो सब से ज्यादा खराब है । यू० पी० में सरप्लस वाटर है, हमारे मुल्क में जितना सरप्लस वाटर है उस का 50 फी सदी यू० पी० में है । अगर, उसी सरप्लस वाटर को एक्सप्लाएट कर लिया गया होता तो इन क्षेत्रों का, जो कृषि क्षेत्र हैं, बहुत भला होता और यू० पी० सारे हिन्दुस्तान को बहुत बड़ी मात्रा में गल्ला दे सकता था, ऐसी स्थिति वहां पैदा हो सकती थी ।

लेकिन जो मैं आपके सामने कुछ आंकड़े रख रहा हूं उनसे आप देखेंगे कि यू० पी० के साथ इसमें भी इमानदारी नहीं बरती गई है । सारे देश में जितना कल्टिवेटेड एरिया है उसका 14 परजेन्ट यू० पी० में है । जबकि यू० पी० में सारे देश के कल्टिवेटेड एरिया का प्रपोरशन 14 परसेंट है लेकिन पहले प्लान में यू० पी० को 11.40 परसेन्ट ही दिया गया, दूसरे प्लान में 6.77 परसेन्ट ही दिया गया और थर्ड प्लान में तो 8.63 परसेन्ट ही दिया गया । और उसमें भी अगर 14 ईस्टर्न डिस्ट्रिक्ट्स का अलग से हिसाब लगाया जाये तो वहां पर इससे भी कम दिया गया । इस तरह से सारे हिन्दुस्तान में जो औसत आता है उससे कम यू० पी० को दिया गया और उसके बाद यू० पी० का भी जो औसत आता है उससे कम उन पूर्वी जिलों को दिया गया । .... **(व्यवधान)** ....

इस हिस्से के पिछड़ेपन के लिए मैं आपके सामने और भी सबूत रखना चाहता हूं । बिजली एक ऐसी चीज है जो कि आजकल तरक्की का एक साधन मानी जाती है । एलेक्ट्रिसिटी के मामले में हिन्दुस्तान का औसत 80 यूनिट के ऊपर है, परहेड कन्जम्शन लेकिन यू० पी० में

[श्री राजदेव सिंह]

सिर्फ 43 है और ईस्टर्न यू० पी० में 30 ही है जो कि बहुत ही कम है ।

इसी के साथ साथ आप इस बात को भी देखें कि पूरे देश में कितने गांव एलीक्ट्रिफाइड किए गए और उसमें से कितने गांव यू० पी० में एलेक्ट्रिफाई हुए और उसमें से कितने गांव पूर्वी उत्तर प्रदेश में एलेक्ट्रिफाई हुए । पहले प्लान में पूरे देश में 3641 गांव एलेक्ट्रिफाइड हुए जिसमें यू० पी० में सिर्फ 23 गांव थे और ईस्टर्न यू० पी० में एक भी गांव नहीं था, जहां की आबादी आज तीन करोड़ है । सेकेन्ड प्लान में 26,900 गांवों में बिजली लगाई गई पूरे देश में लेकिन उत्तर प्रदेश जिसकी आबादी 18 फीसदी है वहां पर सिर्फ 211 गांवों में ही बिजली लगी और ईस्टर्न यू० पी० में सिर्फ कुछ गांवों में ही बिजली लगाई गई । तीसरे प्लान में सारे देश में 54,700 गांवों में बिजली लगाई गई जिसमें से यू० पी० में सिर्फ 50 00 गांवों में और पूर्वी उत्तर प्रदेश के जिलों में शायद कुछ गांवों में बिजली लगाई गई ।

जैसा कि मैंने पहले कहा कि इन 14 जिलों की आबादी तीन करोड़ है और यू० पी० की आबादी इस समय 9 करोड़ है । अब सेन्ट्रल पब्लिक सेक्टर में जो इन्वेस्टमेन्ट हुआ है उसका किस्सा भी सुनिए । पहले प्लान में पूरे देश में सेन्ट्रल पब्लिक सेक्टर में जो इन्वेस्ट किया गया वह था 54.3 करोड़ लेकिन यू० पी० में निल था । दूसरे प्लान में 694.2 करोड़ इन्वेस्ट किया गया लेकिन यू० पी० में निल था । तीसरे प्लान में 1144.2 करोड़ इन्वेस्ट किया गया जिसमें यू० पी० में 72.1 करोड़ था । यू० पी० की पापुलेशन 18 परसेन्ट है लेकिन इन्वेस्टमेन्ट की हालत यह है । सेन्टर से यू० पी० के लिए जो एलाटमेन्ट होना चाहिए था पब्लिक सेक्टर के लिए या दूसरे सेक्टर्स के लिए वह हमेशा कम होता गया है । आज उसी का नतीजा यह है कि यू० पी० पूरा एक प्लान पिछड़ा हुआ है और पूर्वी उत्तर प्रदेश के जो 14 जिले हैं वह तो बहुत ही ज्यादा पिछड़े हुए हैं ।

जो एलाटमेन्ट हुआ है उसी से आप इन्डस्ट्रीज का अन्दाज भी लगा सकते हैं । जहां सारे हिन्दुस्तान में पापुलेशन के लिहाज से इंडस्ट्रियल वर्कर का औसत 4.2 परसेन्ट है वहां यू० पी० में वह 2.1 परसेन्ट ही है । इसी से आप अन्दाजा लगा सकते हैं कि वहां पर इंडस्ट्रीज बहुत ही कम है । वहां पर जो थोड़ा सा परसेन्टेज इन्डस्ट्रियल वर्कर का आता भी है वह शुगर इन्डस्ट्री की वजह से है । लेकिन शुगर मिलों में जो मजदूर काम करते है उनको 12 महीने काम नहीं मिलता है । सिर्फ 6 या 7 महीने ही उनको साल में काम मिल पाता है और बाकी 5 महीने वे बेकार रहते है । एक तरह से वे अन्डर एम्प्लायड है । मैं ने जो परसेन्टेज आपके सामने रखी है उसमें ये वर्कर भी शामिल है । जो इंडस्ट्रीज 12 महीने चलती हैं, अगर उन्हीं के वर्कर्स को लिया जाये तो यह एवरेज और भी कम हो जायेगा ।

अब मैं फ्लड के सम्बन्ध में आपके सामने एक बात रखना चाहता हूं । तीसरे प्लान तक जो फ्लड कन्ट्रोल एलाटमेन्ट हुआ था वह था 147.40 करोड़ । इसमें भी उत्तर प्रदेश के पूर्वी जिलों की अवहेलना की गई । मैं इस अवसर पर अपने जिले की बात भी रखना चाहता हूं । हमारे यहां एक नदी है गोमती जो कि बीच शहर से होकर गुजरती है । उस नदी में हर दूसरे, तीसरे साल बाढ़ आती है और शहर का दो तिहाई हिस्सा उसकी डूब में आ जाता है । उसकी तरफ आज तक कोई ध्यान नहीं दिया गया है । लखनऊ शहर से भी होकर गोमती नदी बहती है लेकिन शहर से दूर बहती है या एक किनारे बहती है । यू० पी० गवर्नमेंट वहां पर बड़े-बड़े बांध बना रही है । जिन्दगी में केवल एक बार ही लखनऊ में बाढ़ आई है, उसके बाद नहीं आई है । जिन जिलों में लगातार बाढ़ आती है वहां पर कोई इन्तजाम नहीं किया गया है । जहां पर बड़े-बड़े

लोग रहते है वहां पर बहुत-सा रुपया खर्च करके सारा इन्तजाम किया गया है ।

इन पूर्वी 14 जिलों में रोड्स भी बहुत कम हैं। पूरे देश में एक लाख की आबादी के पिछे सड़कों का औसत 56 किलोमीटर है जबकि यू० पी० में यही औसत 20 किलोमीटर है और पूर्वी उत्तर प्रदेश में सिर्फ 13 किलोमीटर है । इस प्रकार आय देखेंगे कि वहां पर सड़कें भी बहुत कम हैं ।

जहांतक पर कैपिटा इन्कम का सवाल है, 1951 में सारे देश की पर कैपिटा इनकम 275 रुपए थी लेकिन यू० पी० में 237 रु० और पूर्वी उत्तर प्रदेश में सिर्फ 158 रुपए थी । सन् 1967 में सारे देश में वह बढ़कर 313.10 रु० हुई लेकिन यू० पी० में वह घटकर 227.60 रु० ही रह गई और ईस्टर्न यू० पी० में वह 150 रु० ही रह गई । पूर्वी उत्तर प्रदेश में प्रति व्यक्ति की प्रति दिन की आय का औसत केवल 41 पैसा ही आता है । इससे आप अन्दाज लगा सकते हैं कि दोनों वक्त का खाना तो दूर रहा, एक वक्त का खाना भी कोई कैसे खा सकता है । और फिर इस एवरेज में बड़े लोग भी शामिल हैं जोकि अकेले ही हजारों आदमियों की आय ले लेते हैं ।

जहां तक एजूकेशन का सम्बन्ध है , वहां पर डेढ़ करोड़ लोगों पर सिर्फ एक ही यूनिवर्सिटी है । 416 व्यक्तियों के पिछे केवल एक ग्रैजुएट है । 250 व्यक्तियों के पीछे केवल एक हाईस्कूल पास है और सौ आदमियों के पीछे एक मिडिल पास है । स्टेट लिस्ट में शिक्षा के सम्बन्ध में यू० पी० का 13 वां नम्बर है । . . (**व्यवधान**) अभीतक स्टेट और सेन्ट्रल गवर्नमेन्ट ने मिल करके शिक्षा के ऊपर पूर्वी उत्तर प्रदेश में प्रति व्यक्ति के पीछे केवल 95.50 पैसे खर्च किए हैं ।

आर्थिक दृष्टी से पिछड़े हुए उत्तर प्रदेश के चौदह पूर्वी जिलों के लोग बेहद गरीबी की हालत से परेशान होकर बड़ी भारी संख्या में बड़े-बड़े शहरों की तरफ भागे हैं । आप को सुन कर ताज्जुब होगा कि इन 14 पूर्वी जिलों के 10 लाख लोग बम्बई में है, 5 लाख आदमी कलकत्ते में हैं और कोई 3 लाख आदमी यहां दिल्ली में हैं और इस तरह से दूसरे इंडस्ट्रियल टाऊंस में सब मिलाकर 5 लाख आदमी हैं । इस तरह आप देखेंगे कि करीब 23 लाख आदमी उन 14 जिलों के चूंकि वहां पर उनका गुजर-बसर नहीं होता इसलिए वह वहां से बाहर रोजी की तलाश में बड़े बड़े शहरों में चले गये हैं ।

इन चौदह पूर्वी जिलों में काफी ओवरपापुलेशन है अर्थात् प्रति वर्ग मिल के क्षेत्रफल में 1000 से लेकर 1100 आदमी बसते हैं। अब यह कुदरती है कि जमीन पर बोझ ज्यादा होने से अर्थात् पापुलेशन अधिक होने से वहां पर लोगों के हिस्से जमीन टुकड़े-टुकड़े कर के आ गई है थोड़ी-थोड़ी आती है । इसलिए वहां जो जमीन है, फार्म्स हैं, खेत हैं 80 परसेंट तो अनएकोनामिक होल्डिंग्स हैं और जाहिर है कि,जब लोगों का वहां पर गुजर-बसर नहीं हो सकता तो भागेंगे नहीं तो और क्या करेंगे ? वहां पर रोजी कमाने के लिए दूसरे साधन जैसे कल-कारखाने नहीं हैं । यह उत्तर प्रदेश के उन 14 पूर्वी जिलों की दयनीय स्थिति है जो कि हमारे सामने मुंह बाये खडी है । आखिर ऐसा क्यों हुआ ? इतिहास इस बात का साक्षी है कि अंगेजों के समय जो भी राजनीतिक व क्रान्तिकारी आन्दोलन चले है, कांग्रेस के आन्दोलन चले हैं वह और जगहों के मुकाबले बड़े तेज यहां पर रहे है। आप को याद होगा कि बलिया में सन् 1942 में 7 दिन ब्रिटिश गवर्नमेंट का राज्य नहीं रहा था । सन् 1857 के भारत स्वांतत्रय आन्दोलन में भी उस क्षेत्र के लोग औरों के मुकाबले अधिक लड़े और परिमणास्वरूप जितनी रियासते जब्त हुईं वह भी किसी से छीपा नहीं है । अंग्रेजों ने हमारे उस पिछड़े क्षेत्र की उपेक्षा की यह तो चीज समझ में आती है लेकिन भारत के स्वाधीन होने के बाद अभी जो हमारी इस तरह से उपेक्षा हो रही है वह अलबत्ता समझ में नहीं आ रही है।

दरअसल प्लानिंग जो हुई वह डिफैक्टिव हुई। वह प्लानिंग ऊपर से की गई और नतीजा इसका

[श्री राजदेव सिंह]

यह हुआ कि वह नीचे तक, गांवों तक नहीं गई। इन हमारे प्लानर्स ने मिडिल क्लास के नीचे जहां पर गरीबी थी वहां पर उन्होंने नहीं झांका और वह नीचे गरीबी की लेविल तक नहीं पहुंचे। प्लानिंग के क्षेत्र में देख लीजिये विकास खंड खुले हुए है हर जगह लेकिन मिडिल क्लास के नीचे के तबके की तरक्की के लिए कोई चीज प्लानिंग ने सप्लाई नहीं की।

3 करोड़ के करीब पापुलेशन उत्तर प्रदेश के इन 14 पूर्वी जिलों की है। आंकड़ों को देखने से मालूम होता है कि 19 लाख आदमी दो समय खाना खा लेते हैं, 15 लाख दो समय खाना खा अवश्य लेते हैं लेकिन उनका भोजन बड़ा ही मामूली होता है जबकि 2 करोड़ 75 लाख लोग मुश्किल से एक ही समय खाना खाते हैं। हालत यह है कि इन खाना खाने वालों में से 2 करोड़ लोग ऐसे है जो कि कभी आलू से पेट भर लेते हैं तो कभी शकरकन्द से ही पेट भर लिया करते हैं। कभी वह बेचारे गन्ने के रस से पेट भर लेते हैं और कभी जानवर गाय, बैल आदि जो गोबर करते हैं उस गोबर में से दाने निकाल-निकाल कर उसी से अपना पेट भरते हैं। आम की गुठलियों की रोटी बना कर खाते हैं तो कभी महुआ खाकर वह लोग अपना पेट भर लेते हैं। इसी तरह वहां पर शादी ब्याह के अवसर पर जायं तो आप पायेंगे कि जो वहां पर झूठा फेंका जाता है उस पर छोटे छोटे गरीब बच्चे झपटते है और उन में से दाने निकाल निकाल कर अपने भूखे पेट की ज्वाला को शान्त करने का प्रयत्न करते हैं। यह एक तस्वीर आज उन 14 जिलों की है। जरूरत दरअसल इस बात की है कि वहां पर नीचे से प्लानिंग हो ताकि गरीबों को उस का फायदा पहुंचे। बिजली का ज्यादा से ज्यादा फैलाव वहां पर होना चाहिए। इसी तरह इर्रीगेशन का भी काफी इंतजाम किया जाय और काफी तादाद में पम्पिंग सैट उस एरिया में दिये जायं। जाहिर है कि जो छोटे-छोटे लोगों के खेत है उन में जब वह कैश क्रॉप करेंगे, मल्टीपिल क्रौपिंग करेंगे तभी उन की गुजर-बसर हो सकती है। उन की क्रौप को सही और मुनासिब दाम मिले इसलिए यहां के गांवों को सड़कों से एक दूसरे से मिलाया जाय। जैसा मैंने आप से पहले निवेदन किया इस एरिया के 10 लाख लोग बम्बई में गये हैं, 5 लाख कलकत्ते में गये हैं और 3 लाख के करीब यहां दिल्ली में है अगर उन 14 जिलों में कल-कारखाने होते, इंडस्ट्रीज लगी होतीं तो वह इस तरह से अपने प्रदेश को छोड़ कर बाहर नहीं जाते और वहीं उन मिलों आदि में वह काम करके अपनी रोजी कमा लेते। इस लिये जरूरत इस बात की है कि हर एक जिले में बड़े, छोटे और मध्यम किस्म के कारखाने फैलाव के हिसाब से दिये जायें। हुआ यह कि पार्लियामेंट के मेम्बरों से कुछ कैपिटलिस्टों ने दस्तखत कराये और कहा कि हम कारखाने उत्तर प्रदेश के जिलों में खोलेंगे लेकिन बाद में वह गाजियाबाद उन को ले गये। सरकार को यह भी ध्यान रखना चाहिये था कि जो उद्योगपति पूर्वी जिलों के लिये लायसेंस लें वह उन को वहां से हटायें नहीं, वहीं पर कारखाने खोलें।

रूरल एलेक्ट्रिफिकेशन के लिये रिवाइज्ड फोर्थ प्लान में 534 करोड़ रु० रक्खा गया है। सरकार कोशिश करे कि ज्यादा से ज्यादा इन चौदह जिलों को दिया जाये।

आखीर में मैं यह कहना चाहता हूं कि यू पी एक बहुत बड़ी स्टेट है। चौवन जिले हैं। वहां पर आज गवर्नमेंट बनती है कल टूट जाती है और कुछ हो नहीं पाता है। इसलिये हरियाणा की एग्जाम्पल हमारे सामने है। वहां की सरकार ने तो कमाल ही कर दिया। हर एक गांव में बिजली पहुंचा दी। हम को यह भी बतलाया गया है कि दो साल के भीतर पूरे राज्य में वह मेटल्ड रोड का जाल बिछा देंगे और हर एक गांव तक अप्रोच रोड हो जायेगी। उसने साल दो साल के भीतर यह

काम किया है । यह जो चौदह जिले है पूर्वी उत्तर प्रदेश के वह सारे प्रदेश के सब से पिछड़े हुए जिले हैं । जब तक वहां हर दिशा में काम नहीं किया जाता, हर एक विकास का काम नहीं किया जाता, तब तक हरियाणा की तरह से वहां तरक्की नहीं हो सकती ऐसा न होने पर मुमकिन है कि लोग यह सोचें कि चूंकि हरियाणा की अलग स्टेट हो गई है इसलिये वहां पर जल्दी तरक्की हुई है और वह कोशिश करें इन चौदह जिलों को लेकर एक अलग स्टेट बना दी जाये ।

श्री जनेश्वर मिश्र (फूलपुर) : मेरा व्यवस्था का प्रश्न है । वैसे तो मालूम होता है कि श्रीमती नन्दिनी सत्पथी को जवाब देना है, लेकिन प्रधान मंत्री जी उत्तर प्रदेश की हैं और उत्तर प्रदेश के पिछड़ेपन पर बहस हो रही है । इस लिये उनको बुलवा कर इस बहस का जवाब दिलवाया जाये ।

दूसरी बात यह है कि अगर 6 बजे तक बहस पूरी न हो सके तो मैं प्रार्थना करूंगा कि प्रधान मंत्री से क्या मंत्री महोदय से उत्तर प्रदेश के पिछड़ेपन के बारे में कुछ जवाब दिलवाया जाय । आप उनसे कहे कि कोई रास्ता निकालें और जवाब दे । यह बेचारी क्या जाने उत्तर प्रदेश के बारे में । यह वहां के किसी गांव, मोहल्ले यां शहर को नहीं जानती है ।

THE MINISTER OF STATE (SHRIMATI NANDINI SATPATHY): It is very unfair on the part of the hon. member to say that I do not know anything about UP. I know about UP (*Interruptions*). He should not have made such a statement.

श्री शिव नारायण (बस्ती) : सभापति महोदय, पता नहीं मैं इसको दुर्भाग्य कहूं या सौभाग्य कहूं कि आजादी के बाद से अब तक तीन प्राइम मिनिस्टर उत्तर प्रदेश से आये और तीनों ही इलाहबाद से आये । इसके बारे में मुझे कोई शिकवा या शिकायत नहीं है । अहोभाग्य सफलो मनोरथः मैं उन पूर्वी जिलों से आता हूं जिनके लिये नेहरू गवर्नमेंट ने पटेल कमिशन मुकर्रर किया था । उस समय श्री के. डी. मालवीय मिनिष्टर थे इस गवर्नमेंट में । उन्होंने उसका जो चित्र दिया था उसमें बस्ती जिला 29 जिलों में सब से गरीब जिला था जिस गोवरी आदि का जिक्र श्री राजदेव सिंह ने किया वह उसी जिले का नमूना है । लेकिन इस सरकार के कानों पर अब तक जूं न रेंगी । एक्स-फाइनेन्स मिनिस्टर श्री टी०टी० कृष्णमाचारी वहीं बैठा करते थे जहां आज श्रीमती नन्दिनी सत्पथी बैठी हुई है । वहीं से उन्होंने ऐश्योरेंस दिया था कि हम इन जिलों को टेक अप करेंगे । लेकिन नहीं मालूम वह ऐश्योरेंस किस खत्ते में चला गया । टी०टी० साहब गये और पूर्वी जिले खत्ते में पड़ गये ।

अंग्रेजों के समय में जो चोरी चौरा काण्ड हुआ उसके क्रांतिकारी पूर्वी उत्तर प्रदेश के थे । पूर्वी उत्तर प्रदेश सदा से बागी रहा है । बगावत के नेता चित्तू पाण्डे ने सात दिन तक बलिया में अंग्रेजी हुकूमत से लोहा लिया । हमारे गोरखपुर और बस्ती के इलाके वह इलाके हैं जहां हम ने वह क्रांतिकारी पैदा किये जिन्होंने सारे हिन्दुस्तान में बगावत का झंडा ऊंचा किया । लेकिन जब हमारी नेशनल गवर्नमेंट आई तब उसने भी हमें पीसा और नेगलेक्ट् किया । उन्होंने केवल पंजाब को देखा, हरियाणा को देखा, काश्मिर को देखा जितना रुपया उन्होंने काश्मीर में लुटाया है उतने रुपये में हमारा पूर्वी उत्तर प्रदेश आज एक सब्जबाग हो गया होता ।

यहां क्या है ? अंधेर नगरी चोपट राजा, टके सेर भाजी टके सेर खाजा । यह इस हुकूमत का नक्शा है । इसका जो नतीजा है वह जनता भोग रही है । उत्तर प्रदेश में कांग्रेस की गवर्नमेंट थी । इस गवर्नमेंट ने उसको गिराया । फिर जो बनी उसको इसने गिराया । गवर्नमेंट को गिराना इस सरकार का पेशा हो गया है । इस सरकार को प्रांतीय सरकारों को गिराने से ही फुर्सत नहीं है, तो यह सरकार कैसे उत्थान के कार्य करेगी । इसको तो इसी बात की फिक्र है कि किस तरह से हमारी कुर्सी सलामत रह

[श्री शिव नारायण]

सकती है। देश चाहे जाए जहन्नुम में, इसकी इस सरकार को परवाह नहीं है।

मैं हिसाब आपको बताता हूं। घाघरा नदी को अगर आप बांध दो तो मैं सारे हिन्दुस्तान की चावल की जरूरतें पूरी कर सकता हूं। चार जिले मिल कर, बस्ती, गोरखपुर, देवरियां और आजमगढ़, अगर घाघरा नदी को बांध दिया जाए तो सारे हिन्दुस्तान को चावल खिला सकते हैं, बंगाल को चावल खिला सकते हैं, हमारे यहां काला चावल है। होता है। लेकिन जब उसको पकाया जाता है तो उसमें से बहुत खुशबू आती है। यहां अगर उसको पकाया जाए तो सारे हाउस को उसकी खुशबू जाएगी।

लेकिन दुख की बात यह है कि इस सरकार ने हम को निगलेक्ट किया है। हम शिक्षा के क्षेत्र में पिछड़े हुए हैं, सड़कें हमारे पास नहीं हैं, स्कूल हमारे यहां नहीं हैं। हमारे यहां लड़के मैदान में बैठ कर पढ़ते हैं और बरसात के दिनों में जब वर्षा होती है तो भाग कर अपने गांवों में उनको जाना पड़ता है। यह आलम है, यह नक्शा है। हम उस दुखी इलाके से आते हैं, जहां आपको यह नक्शा देखने को मिलता है। मैं प्रधान मंत्री से मांग करता हूं कि वह यहां आएं और हमारी बातों को सुने। अगर वह यहां अब होती तो उनके दिल में दर्द पैदा होता और हमारे लिए कुछ करतीं। मैं आशा करता हूं कि वह अब भी हमारी दुखभरी आवाज सुन रही होंगी और वह यहां आ कर हमारी बातों का जवाब देंगी।

आप बुन्देलखंड के इलाके को देखें। वहां पीने तक के लिए पानी नहीं मिलता है। 25-25 और 50-50 हाथ नीचे जमीन से पानी निकालना पडता है। औरतें रस्सी की सहायता से पानी खींचते-खींचते तबाह हो जाती है। दो घड़ा पानी अगर उनको निकालना होता है तो उनका दम फूल जाता है। शिक्षा, सड़कों, आदि सभी क्षेत्रों में वह इलाका भी बहुत पिछड़ा हुआ है।

चार पहाड़ी जिले जो हैं वे भी बहुत पिछड़े हुए हैं। में इलैक्शन कम्पेन के सिलसिले में नेनीताल और अल्मोड़ा गया था। वहां की गरीबी को भी मैंने देखा है। वहां ब्राह्मण, ठाकुर आदि लोग भी गरीब हैं और उसी तरह से गरीब हैं जैसे हमारे हरिजन भाई पूर्वी उत्तर प्रदेश में गरीब हैं। मैं समभाव से देखता हूं। सरकार अगर निहायत हमदर्दाना काम करना चाहे तो मैं आश्वासन आपको देता हूं कि आप घाघरा नदी को कन्ट्रोल कर दो, आपको पी एल 480 का अनाज नहीं मंगाना पड़ेगा, आपको अमरीका के सामने बाउल ले कर भीख माँगने के लिए नहीं जाना पड़ेगा।

पूर्वी जिले बहुत पिछड़े हुए हैं। वहां मच्छर हैं, वहां मलेरिया बहुत होता है, तरह तरह के रोग वहां होते हैं। मैं प्रार्थना करता हूं कि भगवान इस सरकार को सद्बुद्धि दे और यह सरकार उधर नजर भी करे। जहां तक चौथे प्लान का सम्बन्ध है, टोटली उस इलाके को निगलैक्ट पहले भी किया गया है बड़े-बड़े विद्वान अफसर बैठे हुए हैं। पता नहीं किस तरह से उसको ये इग्नोर कर देते हैं। मैं चेतावनी देना चाहता हूं कि अगर इस तरह से इग्नोर किया जाएगा तो यह सरकार भी इग्नोर हो जाएगी। उत्तर प्रदेश के 85 मेम्बर हैं। अगली बार भी आने की हिम्मत नहीं कर पाएगा, ऐसा नक्शा बनेगा। जो वहां संविद की सरकार बनी है उसको भी भगवान सदबुद्धि दे और वह हमारी मदद करे। उसको भी मैं बख्शता नहीं हूं। जो शासक का कर्तव्य है उसका उसे पालन करना चाहिये। उसको भी रक्षा करनी चाहिये। यह उसका परम कर्त्तव्य है। इसके विरुद्ध जा कर अगर वह काम करता है तो वह उसका पाप भोगेगा। पूर्वी उत्तर प्रदेश की तरफ आप समभाव से देखें। वहां कोई काम नहीं हो रहे हैं। बीसवर्ष में भी नहीं हुए हैं। वह दबा हुआ है। आप से हम हमदर्दी की मांग करते हैं। समभाव से आप

हमारी तरफ देखें। जो पंजाब को देते हो, वह हमें भी दो। पूर्वी उत्तर प्रदेश के साथ सौतेला व्यवहार नहीं होना चाहिए। ये लोग हमेशा बने रहें, लेकिन हम इंसाफ और न्याय चाहते हैं। "खूब इंसाफ है तेरी अन्जुमने-नाज में, शीशा झुकता है मुंह चूमने को पैमाने का" हम चाहते हैं कि यह सरकार पूर्वी उत्तर प्रदेश को नेग्लेक्ट न करे और देश के सब भागों को समभाव से देखे। इस चर्चा का जवाब चाहे श्रीमती सत्पथी दें और चाहे श्री मिर्धा दें, लेकिन हम चाहते हैं कि हमारी मांगें फुलफिल की जायें और पूर्वी उत्तर प्रदेश को नेग्लेक्ट न किया जाये। वह एक गरीब इलाका है। सरकार उसकी मदद करे। ऐसा करने पर ही सरकार का कल्याण हो सकता है। अगर ये लोग बुद्धिमान हैं, तो समय रहते सचेत हो जायें और ऐसा काम करें, जिस से देश का भला हो।

मैं श्री राजदेव सिंह के कथन का अक्षरशः समर्थन करता हूं।

श्री शम्भू नाथ (सैदपुर): सभापति महोदय, अभी माननीय सदस्य, श्री राजदेव सिंह, ने देश के बैकवर्ड एरियाज और विशेषकर पूर्वी उत्तर प्रदेश के चौदह जिलों की स्थिति की तरफ सदन का ध्यान खींचा है। प्लानिंग कमीशन के द्वारा 1955–56 से ले कर आज तक जब भी सर्वेक्षण किया गया है, पिछड़ेपन में उत्तर प्रदेश के 58 जिलों में से 14 पूर्वी जिलों, 4 पहाड़ी जिलों और बुन्देलखंड के 4 जिलों, इन 22 जिलों का नाम सर्वप्रथम रहा है। माननीय सदस्य ने आंकड़े दे कर साबित किया है कि किस तरह से समूचे उत्तर प्रदेश और विशेषतः 14 पूर्वी जिलों की उपेक्षा की गई है।

इस प्रश्न पर इस सदन में बार-बार चर्चा हुई है। 1962 में गाजीपुर जिले के श्री गहमरी ने इस सदन में रोते हुए उस क्षेत्र की दर्दनाक कहानी सुनाई थी। पंडित जी ने उसको सुनने के बाद एक पटेल आयोग बनाया। दुर्भाग्य से उसी साल चीन ने देश पर चढ़ाई की और उस लड़ाई में पटेल आयोग खटाई में पड़ गया। चाहे उत्तर प्रदेश की सरकार हो और चाहे सेन्टर की सरकार हो, हम बार-बार इस प्रश्न को ले कर वाद-विवाद करते चले आ रहे हैं। लेकिन ऐसा लगता है कि पटेल आयोग ऐसी जगह फैंक दिया गया है कि अब कभी उस पर किसी की निगाह नहीं जायेगी अब मुझे विश्वास हो गया है कि पटेल आयोग हमेशा के लिए खत्म हो गया है।

अभी माननीय सदस्य ने बताया है कि उत्तर प्रदेश के 14 पूर्वी जिलों की आबादी तीन करोड़ है। वहां पर सारा प्रैशर जमीन पर है और 85 फीसदी होल्डिंग्ज अनइकानोमिक हैं। ढाई एकड़ से ज्यादा जमीन किसी के पास नहीं है। तीन करोड़ की आबादी में से एक करोड़ के करीब हरिजन और लैंडलैस लेबरर्ज हैं। गाहे-बगाहे तमाम पार्टियां, कम्युनिस्ट पार्टी, संयुक्त सोशलिस्ट पार्टी, एजीटेशन करती हैं कि भूमिहीनों को जमीन दी जाये। उत्तर प्रदेश के पूर्वी जिलों के लिए यह एक बड़ा भारी सवाल है कि वहां जमीन है नहीं, 85 फीसदी अनइकानोमिक होल्डिंग्ज हैं, बाकी जमीन किसी न किसी तरीके से लोगों ने ले ली है। आज कोई सूरत नहीं है कि उन गरीब हरिजनों और लैंडलैस लेबरर्ज को जमीन मिल सके। मुझे इस बात से खुशी होगी, अगर हमारे एस० एस०पी० के भाई इस सदन में यह एशोरेन्स दें कि अब उत्तर प्रदेश में उनकी सरकार हो गई है, इस लिए अब वे कोशिश करेंगे कि जमीन का समुचित बटवारा किया जाये, जिस के लिए उन्होंने एजीटेशन किया और जेल में गये। लेकिन मुझे उम्मीद है कि न कर पाए हैं और न कर पाएंगे क्योंकि हम ने इसके पहले भी देखा है....

श्री राम सेवक यादव: दिल्ली में ले लो, बंगाल में ले लो, बिहार में ले लो जहां तुम्हारी सत्ता है और देवी जी से यहीं दिल्ली में ले लो जहां डा० कर्ण सिंह का फार्म है, श्रीमती इंदिरा गांधी का फार्म है और केशवदेव मालवीय का फार्म है, सभी का है, वह पहले ले लो।

श्री शम्भूनाथ: तो यह तो लैंडलेस की प्राबलम है। हमारे भाई राजदेव सिंह ने आप के सामने बताया कि हमारे पूर्वी उत्तर प्रदेश के एक आदमी की आमदनी 41 पैसे प्रति दिन है। मैंने आपके सामने यह भी अर्ज किया कि हरिजन और लैंडलेस लेबरर कितने हैं। अभी इन्होंने बताया कि एक टाइम खाने वालों की संख्या 2 करोड़ है, उसमें 90 प्रतिशत हरिजन और लैंडलेस लैबरर्स हैं। सवाल बड़ा अहम है। हमारे यहां इंडस्ट्री नहीं है। हमारे यहां लैन्ड प्राबलम साल्व नहीं हो सकती क्योंकि लैन्ड है नहीं और जो कुछ भी है वह या तो किसी तरीके से चली गई है या चूंकि उत्तर प्रदेश में आए दिन सरकार बदलती हैं तो कोई उम्मीद नहीं है कि जमीन का कोई साल्यूशन हो सकेगा, इसलिए मैं अपने मंत्री महोदय से यह बिनती करूंगा कि यह बड़ा अहम मसला है, जैसा कि अभी आपके सामने कहा गया, हमारे पूर्वी जिलों में इस तरह की बात फैल रही है, लोगों के दिमाग में आ रहा है कि हमारी बराबर 20 वर्षों से उपेक्षा की जा रही है, देश की आजादी के लिए इस हिस्से के लोगों ने सब से ज्यादा कुर्बानी की है और इसी के साथ इस तरह उपेक्षा बरती जा रही है तो उन के दिमाग में यह बात आ रही है कि हमारे हिस्से को अलग कर दिया जाय क्यों कि उत्तर प्रदेश में इस समय राजनैतिक अस्थिरता बराबर फैल रही है जिस का परिणाम यह है कि 1967 से आज तक कोई विकास का काम उत्तर प्रदेश के पूर्वी जिलों के लिए नहीं हुआ है और न होने की उम्मीद है। यह बात वहां के लोगों के दिमाग में पैदा हो रही है। लोग चाहते हैं और इस तरह की आवाज बुलन्द कर रहे हैं कि हमारे उत्तर प्रदेश को बाइफरकेट कर दिया जाय, इसका डिवीजन कर दिया जाय तभी हमारा कल्याण हो सकता है क्योंकि अभी तक हमारा कोई कल्याण नहीं हुआ है।

श्री रामसेवक यादव: बंटवारे की लड़ाई में इस सरकार का भी कल्याण है क्योंकि कुछ दिन और बच जायेगी।

श्री शम्भूनाथ: मैं जमीन के मुताल्लिक कह रहा था कि जमीन आप दे नहीं सकते और दूसरा कोई और तरीका आपके पास है नहीं। तो मैं सरकार से एक बात कहना चाहता हूं, चाहे वह उत्तर प्रदेश की सरकार के द्वारा हो चाहे यहां की सरकार के द्वारा हो, मैं तो कहूंगा कि उत्तर प्रदेश की सरकार नहीं कर सकी है न कर सकेगी, जो मौजूदा सरकार है उस से भी उम्मीद नहीं है, तो यहां की सरकार पूर्वी उत्तर प्रदेश के लिए एक डैवलपमेंट बोर्ड अलग से बनाए। मैं इसलिए चाहता हूं कि 20 वर्षों से प्लान एलौकेशन 60 प्रतिशत हुआ जनसंख्या के हिसाब से और 10 प्रतिशत हुआ रीजनल इम्बलैन्सेज के हिसाब से। 70 प्रतिशत जो प्लान एलौकेशन हुआ अगर उस के आधार पर हमारे उत्तर प्रदेश के जो पूर्वी जिले हैं उनको मिले तो इस फोर्थ फाइव ईयर प्लान में हमारे ये 14 जिले बहुत जल्दी तरक्की कर जाएंगे। लेकिन हो क्या रहा है? उलटा हो रहा है। आपको सुन कर ताज्जुब होगा कि प्लानिंग कमीशन ने इन 14 जिलों को बैकवर्ड माना लेकिन जब इन के उत्थान की बात आई तो मुझे दुख के साथ कहना पड़ता है कि इन 14 जिलों को छोड़ कर अभी के चन्द महीने पहले बदायूं और कुछ दूसरे जिले ले लिए गए..

श्री राम सेवक यादव: कौन जिम्मेदार था जब बदायूं और दूसरे जिले लिए गए?

श्री शम्भूनाथ: तो यह अन्याय हमारे साथ हो रहा है। हम को डिक्लेयर किया जाता है मोस्ट बैकवर्ड डिस्ट्रिक्ट्स और जब हम को देने का सवाल आता है तो पैसा दूसरी तरफ चला जाता है। अब जिस की सरकार भी हो, मैं उस में नहीं पड़ना चाहता लेकिन ऐसा हो रहा है।

सभापति महोदय, एक बात मुझे और रखनी है। हमारे उत्तर प्रदेश में शुगर इंडस्ट्री है—महज एक इंडस्ट्री, जिसमें कुछ लोग एम्प्लाएड हैं। इस समय आलम यह है कि जितने शुगर-मेगनेट्स हैं, वे हमारे किसानों को लूट रहे हैं,

आज तक उनका अपटू-डेट पेमेन्ट नहीं हुआ है, सारा पैसा उनके पास पड़ा हुआ है। मैं इस सरकार से और खास कर उत्तर प्रदेश में जो मौजूदा सरकार है, जिसके एस०एस०पी० वाले भी पार्टनर हैं, उनसे अनुरोध करना चाहता हूं कि शुगर इंडस्ट्री को जल्द से जल्द नेशनलाइज किया जाय, उसके बिना नेशनलाइजेशन के हमारे उत्तर प्रदेश का कल्याण नहीं होगा....

श्री राम सेवक यादव : सभापति महोदय, मैं तो यह चाहूंगा कि यह सरकार जो यहां बैठी है, पूरे देश के चीनी उद्योग के राष्ट्रीकरण के लिये एक नीति बनाये, मैं जानना चाहता हूं कि ऐसा करने में इन को कौन सी ताकत रोकती है....

श्री शम्भूनाथ : चूंकि कुर्सी पर बैठ गये हैं, इसलिये ऐसी बात कह रहे हैं । सभापति महोदय, हमारा समय जा रहा है, हमें अभी हरिजनों और लैण्डलेस लेबरर्स के बारे में कहना है । हमारे देश में हरिजनों और लैण्डलेस लेबरर्स के पास इस समय कोई भी जरियाये-मुआश नहीं है । अगर उनकी हालत को सुधारना है तो कोआपरेटिव बेसिज पर स्माल स्केल इंडस्ट्रीज की व्यवस्था करें, ताकि उनको आजीविका मिल सके और उनकी जिन्दगी खुशहाल हो सके ।

सभापति महोदय, जैसा मैंने अभी कहा था, अगर इस मौजूदा हालत में हमारे पूर्वी उत्तर प्रदेश के इन 14 बेकवर्ड जिलों का ख्याल नहीं किया गया, तो आज जो भावना उनके मन में पैदा हो रही है, उसका इजहार हमारे दिल्ली शहर में करीब 3 लाख में से 40 हजार लोगों ने 30 अगस्त को एक बहुत बड़ा जलूस निकाल कर दिया था, वे प्रधान मंत्री जी के निवास स्थान पर गये और उनके सामने उन्होंने अपनी बात रखी कि किस तरह से उनकी उपेक्षा की जा रही है और यह खुशी की बात है कि हमारी प्राइम मिनिस्टर साहिबा ने हमारे उन डिमांस्ट्रेटर्स को काफी समय दिया, 45 मिनट से ज्यादा समय देकर उनको सम्बोधित किया और एशोरेंस दिया कि ये 14 जिले जो पिछड़े हुए हैं उन पर अवश्य ध्यान दिया जायगा ।

श्री रणजीत सिंह (खलीलाबाद) : सभापति जी, मैं उन सदस्यों को धन्यवाद देना चाहता हूं जिन्होंने इस मामले को उठा कर उत्तर प्रदेश के पिछड़ेपन की तरफ सदन का ध्यान खींचा । बहुत दिनों से यह मामला इस सदन में बार-बार उठ चुका है । जो आंकड़े श्री राजदेव सिंह जी ने आप के सामने रखे, उनसे आपने देख लिया कि देश में जितने भी पुराने पिछड़े हुए इलाके चले आ रहे हैं, आज भी उनमें सब से पिछड़ा हुआ प्रदेश उत्तर प्रदेश है और उत्तर प्रदेश में भी सब से पिछड़े हुए 22 जिले हैं, जब कि देश के सभी भागों में उस प्रकार के जिलों की संख्या केवल 49 मानी गई है । इसका मतलब है कि देश के सारे पिछड़ेपन का 40 फीसदी केवल हमारे उत्तर प्रदेश में है, जिसमें से 14 जिले केवल ईस्टर्न यू०पी० के हैं । हमारे लिये यह बड़े शर्म की बात होती है जब हम किसी को उन क्षेत्रों में दिखलाने के लिये ले जाते हैं—ऐसा महसूस होता है कि यह कैसा आजाद देश है, यहां कैसी सरकार है, जहां मनुष्यों की दशा जानवरों से भी बदतर है ।

सभापति महोदय, आपको भी बतलाया गया है कि जानवरों के मल में से दाना निकाल कर वहां के लोग खाया करते हैं, ऐसी भीषण गरीबी अभी भी वहां पर है । लेकिन भारत सरकार के चन्द ऐसे विभाग हैं जो ऐसे इलाकों को भी पिछड़ा नहीं मानते । अभी हाल में डेवलपमेंट कमिश्नर, स्माल स्केल इंडस्ट्री ने अपना एक सर्कुलर भेजा है, जिसमें उन्होंने उत्तर प्रदेश के पूर्वी जिलों में से सात जिलों को छांटा है, लेकिन उसमें से उन्होंने बस्ती जैसे पिछड़े जिले की हस्ती को ही मिटा दिया है, कहीं उसका नाम ही नहीं है। बहराइच का कहीं नाम नहीं है, गोरखपुर का कहीं नाम ही नहीं है, देवरिया का कहीं नाम नहीं है, आजमगढ़ का कहीं नाम नहीं है । गोंडा का गलती से या पता नहीं कैसे आ गया । मेरा कहने का मतलब यह है कि इस पिछड़ेपन का जो एक

[श्री रणजीत सिंह]

नतीजा रहा है वह यह भी रहा है कि सरकारी अधिकारियों में विशेषकर ऊंचे सरकारी अधिकारियों में पूर्वी जिलों के लोग नहीं रहे हैं और इस कारण उसकी उपेक्षा होती रही है। आप यही देख लीजिए, उत्तर प्रदेश के पिछले चार चीफ सेक्रेटरी और उसके पहले के लोगों के बारे में मैं नहीं जानता, सबके सब पश्चिम से रहे हैं। इसीलिए ऐटामिक पावर प्लान्ट जाना हुआ तो वह पूरब में नहीं पश्चिम में दिया गया। अभी दिया तो नहीं गया लेकिन उम्मीद दिलाई गई है, वह भी पश्चिम में दिया जा रहा है। उससे जो बिजली होगी, कामन ग्रिड बन जायगा तो सब जगह दी जायगी लेकिन उसके साथ 920 करोड़ रुपये का डेवलपमेंट प्लान है वह बजाय पूर्वी उत्तर प्रदेश और पहाड़ी तथा बुन्देलखंड के जिलों को देने के सब का सब पश्चिमी उत्तर प्रदेश में दे दिया गया है। अवहेलना का एक और मैं उदाहरण देता हूं। मेरे जिले में, बस्ति में जिस की आबादी इस समय 37 लाख आंकी जाती है, उत्तर प्रदेश का सब से घनी आबादी वाला जिला. 37 लाख की आबादी वाले उस जिले में चौथी योजना में सड़क बनाने के लिए 35 किलो मीटर की योजना है जब कि जहां पहले ही 1600 किलो मीटर सड़क है, उस मुजफ्फरनगर में 136 किलो मीटर नई सड़क बनाने की योजना है। तो इस प्रकार से उपेक्षा होती है। मैं यह नहीं चाहता हूं कि किसी का हिस्सा काट कर के हम को मिले या हमारी उन्नति किसी की अवनति के ऊपर की जाय। लेकिन जहां पर भी किसी भी प्रदेश का चित्र सामने रखा जाता है तो यह जरूर देखना चाहिए कि वहां कोई क्षेत्रीय असंतुलन न रहे जैसे सारे देश में भी कोई क्षेत्रीय असंतुलन नहीं रहना चाहिए। यह कहा जाता है कि पूर्वी उत्तर प्रदेश के लिए हम ने रिहैड की योजना बनाई। सरकार ने कुछ दिन पहले कहा कि हमारे पास पर्याप्त बिजली है, जब लाइन बिछ जायगी तो गांव-गांव बिजली हो जायगी। एक बार प्रश्न के उत्तर में उत्तर प्रदेश सरकार ने बताया था कि हमारे पास इतनी बिजली है कि अब हम वह बिजली रेलवे को दे रहे हैं। लेकिन अब जब पूछा जा रहा है कि कनेक्शन क्यों नहीं मिलते तो कहा जाता है कि पर्याप्त बिजली हमारे पास नहीं है और केन्द्र हमारी कोई मदद करने को तैयार नहीं है। हम को तो सब से बड़ा ताज्जुब इस बात से होता है कि एक साल के अन्दर तामिलनाडू को 80 करोड़ रुपया मिल गया लेकिन उत्तर प्रदेश को 80 पैसे भी यह सरकार नहीं देना चाहती जब कि उत्तर प्रदेश के संसद सदस्यों के बल पर यह सरकार टिकी हुई है। तो मैं तो यह प्रार्थना करूंगा कि अगर कोई अनुदान नहीं देना है तो कम से कम हमारी बिजली तो छोड़ दे यह सरकार, रेलें तो डीजेल और स्टीम पावर से भी चल सकती हैं, जिस बिजली की हमें कमी है वह बिजली हमें वापस कर दे। कई बार प्रधान मंत्री ने अपने भाषणों में कहा, जो दस दस मिनट का भाषण दिया करती हैं, उत्तर प्रदेश में कई बार उनके भाषणों में यह बात आई कि उत्तर प्रदेश इसलिए विकास नहीं कर पाया कि 1962 में चीन ने आक्रमण कर दिया तो विकास का काम ठप हो गया, फिर 1965 में पाकिस्तान ने आक्रमण कर दिया तो सारा विकास रुक गया, तो मैं यह पूछना चाहता हूं कि यह बहाना केवल एक उत्तर प्रदेश के लिए ही था? क्या यह बहाना केवल पूर्वी उत्तर प्रदेश के लिए ही था? अब मुश्किल यह हो जाती है कि वहां की गरीबी का अन्दाज हमारी प्रधान मंत्री को नहीं हो पाता है हालांकि वह वहीं की रहने वाली हैं। यहां पर जो पक्षपात किया जाता है उत्तर प्रदेश के हितों के खिलाफ उसका और एक नमूना मैं आप के सामने पेश करना चाहता हूं। उत्तर प्रदेश के एक मेधावी व्यक्ति पी० एन० सिंह ने जो जर्मनी में एक स्कूटर कारखाने में काम करते थे यहां पर आ कर सरकार के सामने एक योजना रखी कि वह देशी कल पुर्जों से ही, बिना विदेशी कोई चीज

निर्यात किए हुए स्कूटर तैयार कर देंगे, उनको कारखाना बनाने की इजाजत दी जाय, लेकिन उनको इजाजत नहीं दी गई। खैर, खुशी की बात है कि उत्तर प्रदेश की एक बेटी के बेटे को छोटी कार बनाने की इजाजत मिल गई है।

मैं इस सरकार से प्रार्थना करूंगा कि वह पूर्वी उत्तर प्रदेश में और कुछ नहीं तो कम से कम फैक्टरी तो लगा दे लेकिन दुख का विषय है कि फैक्टरीज वहां पर न लगाई जाकर हरियाणा में ले जाई जा रही हैं।

सभापति महोदय, प्रधान मंत्री महोदया को वहां की गरीबी का अंदाज नहीं लग पाता है हालांकि वह दौरे बहुत करती हैं, क्योंकि जब प्रधान मंत्री जाती हैं तो महीनों पहले से लोग उसकी तैयारी करते हैं। वहां के लोग सोचते हैं कि भाई हम चूंकि प्रधान मंत्री के सम्मुख जा रहे हैं इसलिए जिस गरीब के पैर में जूता नहीं होता है वह दूसरे का मांग कर पहन लेता है और फिर जाता है, कपड़े धोकर जाता है, गरज यह कि अपने सब से सुन्दर वेश में वह प्रधान मंत्री के सम्मुख जाता है। उसे देख कर प्रधान मंत्री को वास्तविक स्थिति का अंदाजा नहीं लग पाता है और प्रधान मंत्री समझती हैं कि उत्तर प्रदेश का बड़ा विकास हो गया है। मैं खुले हृदय से बिना किसी राजनीतिक कारण के श्रीमती नन्दिनी सत्पथी को अपने इलाके में आने के लिए निमंत्रित करता हूं कि और वहां आने के बाद उनको वास्तविक स्थिति का सही अंदाजा लग सकेगा। जब वह वहां के धूल धूसरित क्षेत्रों में घूमेगी, वहां की धूल फांकेंगी तब उन्हें पता चलेगा कि पिछडापन किस को कहते हैं और उनको भी शर्म आयेगी। कुछ उनको शर्म इस बात की भी आयेगी कि आज वह उस सरकार का समर्थन कर रही हैं जोकि इस सब के लिए जिम्मेदार है।

श्री अटल बिहारी वाजपेयी (बलरामपुर) : कम से कम वह एक सुन्दर कहानी तो जरूर लिख देंगी।

श्री रणजीत सिंह : अन्त में मैं इतना कहना चाहूंगा कि धन की धारा उलटी बहती है **मनी फ्लोज इन दी रिवर्स डाइरेक्शन**, और जितनी भी चीजें हैं सब की धारा हाएर पोल से नीचे पोल की तरफ चलती है जैसे कि बिजली और पानी के लिए कह सकते हैं लेकिन धन एक ऐसी चीज है जिसकी धारा उलटी बहती है। आप एक प्रगतिशील इलाके को एक पिछड़े इलाके के साथ बांध कर यदि प्रगति करना चाहेंगे तो पिछड़ा इलाका और गरीब होता चला जायगा और जो आगे बढ़ा हुआ इलाका है वह और भी अमीर होता चला जायगा। अगर आप भारत का नक्शा उठा कर देखेंगे तो पायेंगे कि जहां पंजाब आगे बढ़ता चला जा रहा है वहां उसकी बगल का हरियाणा गरीब होता चला जा रहा है लेकिन जब से हरियाणा अलग हो गया तब से वह प्रगति कर रहा है। बाकी यह बात दूसरी है कि वह जो उनका एलेक्ट्रिफिकेशन प्रोग्राम है उसमें प्रोपेगैंडा ज्यादा है और बिजली की रोशनी कम है।

आज उत्तर प्रदेश इतना बड़ा प्रदेश है लेकिन फिर भी कोई उसके बंटवारे की मांग हम नहीं उठा रहे हैं लेकिन यह मांग जरूर उठा रहे हैं कि इस असन्तुलन को समाप्त करने के लिए इस उत्तर प्रदेश के पूर्वी जिलों को अर्थात् इस पिछड़े प्रदेश को पश्चिमी उत्तर प्रदेश के विकसित क्षेत्र के साथ मिला कर यदि आप प्रगति करना चाहते हैं तो उसका एक ही तरीका है कि उसके लिए एक अलग डेवलपमेंट बोर्ड बनाय। जाय। उत्तर प्रदेश के पूर्वी जिलों के लिए एक अलग बोर्ड बनाये, बुन्देलखड के लिए एक अलग बोर्ड बनायें और पहाड़ी क्षेत्रों के लिए अलग बोर्ड बनायें। लेकिन जब यह बोर्ड आप बनाते हैं तो उस में धन केन्द्रीय सरकार से जाना चाहिए और केन्द्रीय सरकार को अपने माथे पर से यह कलंक धो डालना चाहिए जोकि उस

[श्री रणजीत सिंह]

के लगा हुआ है । इससे बढ़ कर कलंक की बात और क्या हो सकती है कि पिछले 23 वर्षों से हालांकि वह शासन करते आये हैं और उत्तर प्रदेश से ही प्रधान मंत्री बनते आये हैं लेकिन तो भी पूर्वी उत्तर प्रदेश में इतना पिछड़ापन बाकी है ।

अन्त में मैं यह कहना चाहता हूं कि मेरे मित्र जोकि शासक कांग्रेस दल में हैं और चूंकि वह इस से पीड़ित हैं इसलिए उन्होंने इस विषय को आज यहां पर उठाया है उनसे मेरी यह गुजारिश है कि महज चिल्लाने से या रोने धोने से कुछ नहीं होने वाला है । यह सरकार लाठी की भाषा समझती है और लाठी न हो तो कम से कम उसे आंख तो दिखाई जाय, अगर काटा न जा सके तो कम से कम फुफकार तो मार ही दी जाय और फुफकार मार कर देखो तो तुम को सब कुछ मिलेगा ।

MR. CHAIRMAN : Shri Janeshwar Misra.

SHRI UMANATH (Pudukkottai) : Sir, now that there are only five or six minutes to six o' clock, please do not adjourn the House at six o' clock because this discussion is under rule 193 and there are already many incomplete discussions under rule 193 pending.

श्री रामसेवक यादव (बाराबंकी) : सभापति महोदय, इस पर विचार के लिए समय और बढ़ा दिया जाय । यह बड़ा महत्वपूर्ण सवाल है । यह केवल उत्तर प्रदेश के पूर्वी जिलों का ही नहीं अपितु देश के सभी पिछड़े प्रदेशों का मामला है इसलिए इस पर एक घंटे का समय बढ़ा दिया जाय ।

MR. CHAIRMAN : Yes, if the House is in favour of sitting for another hour.

श्री जनेश्वर मिश्र (फूलपुर) : सभापति महोदय, ऐसे तो सारा देश ही पिछड़ा हुआ है और पिछड़ा इसलिए है कि इस सरकार की देश के लिए जो योजना वाली नीति रही है वह सारी दोषपूर्ण थी ।

उत्तर प्रदेश के बारे में खास तौर से अभी चर्चा करते हुए एक, दो लोगों ने छींटाकशी की कि उत्तर प्रदेश ने देश को तीन प्रधान मंत्री दिये । मेरा यह खयाल है कि उत्तर प्रदेश ने न केवल प्रधान मंत्री दिया है बल्कि सारे हिन्दुस्तान के रेलवे स्टेशनों पर कुली दिया है, सारे हिन्दुस्तान को चपरासी दिया है । इस सदन को अगर उत्तर प्रदेश के लोगों ने प्रधान मंत्री दिया है तो इस सदन में जितने चपरासी हैं, आप देख लीजिये सभी के सभी उत्तर प्रदेश के हैं । यह बहुत ही बड़ी विडम्बना है । ऐसा लगता है कि उत्तर प्रदेश के राजनीतिक कमल के फूल की खेती करते हैं जिसमें एक कमल खिलता है, पहले कमल खिला करते थे अब कमलिनी खिल रही है, और उसके नीचे गरीबी, दुःख, परेशानी और रोग का अपार दलदल है । उसको आप ऐसा मत समझिएगा, गोबर वाले दाने की बात तो इन लोगों ने कही ही है, कभी आप बनारस के मणिकर्णिका घाट पर जायें तो देखेंगे कि वहां गायें घूमती रहती हैं । इसलिये कि वहां जो लाशें जलती हैं उनमें से अधजली लाशें खाने में ज्यादा सोंधी होती हैं और वह उन गायों का चारा है । जहां गाय आदमी की लाश खाती हैं, जहां पर आदमी जिस आम को जूठा कर के फेंक देते हैं उसकी गुठली को निकाल कर और रोटी बना कर खाते हैं, बैल के गोबर का दाना निकाल कर उसकी रोटी खाते हैं, इसका दोषी आखिर कौन है ? यह हम को सोचना पड़ेगा ।

यह बहस छिड़ी, और पिछले साल डेढ़ साल से छिड़ रही है, जब उत्तर प्रदेश के मुख्य मंत्री और दिल्ली के प्रधान मंत्री में राजनीतिक टकराव हुआ चन्द्रभानु गुप्त के जमाने से । जब यह बहस छिड़ी तो गुप्त साहब ने कह दिया कि दिल्ली उत्तर प्रदेश की तरक्की में बाधा दे रहा है और दिल्ली वाली ने कहा

दिया कि लखनऊ उत्तर प्रदेश की तरक्की में बाधा बन रहा है। इस तरह से बराबर चल रहा है। आज मैं यह चाहता था कि प्रधान मंत्री यहां होती और वह एक-एक कारण गिनाती कि उत्तर प्रदेश की लखनऊ वाली सरकार ने इस इस तरह से उत्तर प्रदेश की तरक्की में बाधा पहुंचाई है। यह सच है कि सारे हिन्दुस्तान के राजनेताओं ने उत्तर प्रदेश के लोगों को प्रधान मंत्री का एक गुड्डा या गुड़िया दे दी, और उसके बाद विकास की जितनी चीजे थीं झपट्टा मार नीति चला कर उत्तर प्रदेश को सारे हिन्दुस्तान की दौलत से निकाल कर खींच लिया है। उन्हें इस को गिनना चाहिये। मैं तो चाहता हूं कि आबादी के हिसाब से सड़कें बनें, आबादी के हिसाब से रेलें हों, आबादी के हिसाब से स्कूल, आबादी के हिसाब से दवा और अस्पताल हों। उत्तर प्रदेश में कितने अस्पताल बने हैं अगर इसकी जांच कर के कोई रिपोर्ट बनेगी तो पूर्वी उत्तर प्रदेश की कितनी बुरी हालत होगी, इसका आप अन्दाजा नहीं लगा सकते हैं। मैं जिस क्षेत्र से आता हूं, उसमें पहले प्रधान मंत्री रहा करते थे। वहां एक भी सड़क नहीं है, कायदे से एक भी स्कूल में छप्पर नहीं है, पूरे फूलपुर के गंगाघर इलाके में रेलवे स्टेशन पर वेटिंग रूम नहीं है। आखिर वह कहां बन कर जाता है, किस जगह पर बनता है। आखिर यह पैसा जा कहां रहा है यह मेरी समझ में नहीं आता। अभी भी वहां जाने पर लोग यह सवाल करते हैं।

इन सारी बातों के होते हुए उत्तर प्रदेश की तरक्की अकेले इसी से नहीं हो जायेगी कि प्रधान मंत्री या नन्दिनी जी कुछ पैसा दे देंगी लखनऊ को। सच तो यह है कि उत्तर प्रदेश के जो लोग इस समय राजनीति चला रहे हैं उनका मन और मिजाज इतना गन्दा हो गया है, खास तौर से ताकतवाली राजनीति चलाने वाले जो लोग हैं, जिसका ठिकाना नहीं है। आप देखेंगे कि आज से पच्चीस साल पहले उत्तर प्रदेश के जो लोग हिन्दुस्तान के नेता थे उन के बेटे और बेटियां सारे हिन्दुस्तान के फिर से नेता बन गई। किसी दूसरे सूबे में आप यह रोग कम पायेंगे। ऐसा नहीं है कि राजेन्द्र बाबू का बेटा राष्ट्रपति बनने की ख्वाहिश करता हो, जाकिर हुसेन का बेटा ऐसा करता हो या जगजीवन राम का बेटा ऐसा करता हो अथवा कामराज का बेटा ऐसा करता हो, लेकिन उत्तर प्रदेश से जो निकला... (**व्यवधान**)

एक माननीय सदस्य : कामराज तो अविवाहित हैं।

श्री जनेश्वर मिश्र : गांधीजी के भी बेटे थे। उन्होंने भी राजनीति में कोई हविस नहीं की। लेकिन उत्तर प्रदेश की राजनीति में जो कोई निकला है, प्रधान मंत्री या मालिक बना है, उसके बेटे बेटियां क्या करती हैं? यह जनतन्त्र है? क्या यहां पर आप विरासत चलाना चाहते हैं? यह कैसे चल सकता है? मैंने एक दिन यह बात छेड़ी थी। मैं नाम नहीं लेना चाहता। इलाहाबाद के एक नेता हैं और आप की पार्टी के जनरल सेकेट्री हैं। उनका बेटा केवल पन्द्रह महीने पहले वकालत पास किये हुए है, बी. आई सी. का, जो पहले मूंदड़ा वाली कम्पनी थी, सरकारी वकील बन गया है। कहना मैं नहीं चाहता था, प्रधान मंत्री जब आनन्द भवन का दान करने गई तब वहां तीन दिन तक रहीं। एम. आर. शेरवानी के यहां दावत खाने के लिये गई। शेरवानी साहब ने उनकी सोनिया बहू को एक हार दिया, और उसके तीन दिन बाद शेरवानी साहब को कारवन राड फैक्ट्री का लाइसेन्स दिया गया (**व्यवधान**) मैं देश के पिछड़ेपन का बखान कर रहा हूं।

SHRI RANDHIR SINGH (Rohtak) : This should not be allowed. I strongly protest against it. He is so irrelevant. It must be expunged.

श्री रामसेवक यादव : इनको प्रोटेस्ट करने दीजिये। इसमें कोई ऐसी चीज नहीं है जो डीसेंसी के खिलाफ हो।

18 hrs.

SHRI K. N. TIWARY (Bettiah) : I requested you at that time also that if any Member wants to bring any charge, he must give notice.

MR. CHAIRMAN : Please resume your seat,

SHRI RANDHIR SINGH : Would you allow him to say all this ?

श्री तुलशी दास जाधव (बारामती) : हाउस में डिगनिटी कायम रहे, इस वास्ते रूल्ज बने हुए हैं । बात करने का कोई तरीका भी होता है और उसके बारे में रूल्ज बने हुए हैं।

SHRI RANDHIR SINGH : You must discourage this tendency in the House, Sir. We will not allow anybody to abuse our leaders here. गाली को हम एलाऊ नहीं कर सकते हैं ।

SHRI RANJEET SINGH : Is Sonia your leader ?

श्री राम सेवक यादव : खुशामद को आप एनकरेज करते हैं ?

श्री रणधीर सिंह : बेहूदगी जो यहां होती है, जो गालियां दी जाती हैं, उसको हम बरदाश्त नहीं कर सकते हैं ।

श्री तुलशी दास जाधव : इतने बड़े हाउस में जब आपस में हम बोलते हैं तो किसी का नाम ले कर छोटी-छोटी बातों को ले कर और किसी को बदनाम करने का प्रयत्न करना ठीक नहीं है । प्राइम मिनिस्टर कहां गई, क्या किया इसका मतलब यह है कि एक इंडिविजुअल को ले कर ये पालिटिक्स अपना चलाना चाहते हैं—

MR. CHAIRMAN : There is no point of order. Please resume your seat.

SHRI SHAMBHU NATH: Point of order, Sir.

MR. CHAIRMAN : What is the point of order ?

श्री तुलशी दास जाधव : आप मेरी बात तो सुन लें ।

श्री राम सेवक यादव ; अपने लीडर की खुशामद करना यही इनकी राजनीति है ।

श्री रणधीर सिंह : हम अपने लीडर की करेंगे । अगर ये उसको गाली देंगे तो मैं पचास गालियां दूंगा इनको । आप इनको कंट्रोल करें। कोई लिमिट तो होनी चाहिये ।

श्री तुलशी दास जाधव : मैं यह कह रहा था कि पार्लियामेंट में कोई बात करनी है किसी इंडिविजुअल का नाम ले कर और छोटी-छोटी बातों को उठाना है उसके घर की बात को ले कर तो यह ठीक नहीं है। प्राइम मिनिस्टर की एस० एस०पी० वाले बार-बार बात करते हैं । बाकी सब पालिटिक छोड़ कर बार-बार यह जो घराना, नेहरू घराना की बात करते हैं, यह बड़ी बुरी बात है और इस तरह की बातें करना ठीक नहीं है।

सभापति महोदय : आप बैठिये । कोई प्वाइंट आफ आर्डर नहीं है । श्री शम्भू नाथ।

श्री शम्भू नाथ : मेरा प्वाइंट आफ आर्डर है । इन्होंने प्राइम मिनिस्टर का नाम लिया । उस पर हमें कोई विरोध नहीं है । जहां तक दूसरा नाम लिया इन्होंने उसके बारे में मेरा आप से अनुरोध है कि वह नाम रिकार्ड में से एक्सपंज किया जाए ।

श्री रणधीर सिंह : सारा एक्सपंज किया जाए । सारी बातें गलत हैं । सब एक्सपंज होनी चाहियें । अगर फिर कहेंगे तो हम इनको बोलने नहीं देंगे ।

श्री राम सेवक यादव : क्या किसी मेम्बर को यह कहने का हक है कि हम बोलने नहीं देंगे ।

श्री रणधीर सिंह : नहीं बोलने देंगे । गालियां सुनने के लिए हम नहीं आए हैं ।

अगर गालियां दी जाएंगी तो हम भी गालियां देंगे। श्री अटल बिहारी वाजपेयी हैं, श्री लिमये हैं, हमारे कम्युनिस्ट पार्टी के लीडर हैं, हम उनकी इज्जत करते हैं। लेकिन ये जो गालियां देते हैं, इसको हम टालरेट नहीं करेंगे।

MR. CHAIRMAN : I am conducting the proceedings. Please resume your seat.

SHRI RANDHIR SINGH : That is all right. You must control them. We respect you. But we will not tolerate all this.

MR. CHAIRMAN : Please resume your seat now.

Mr. Misra.

SHRI DWAIPAYAN SEN (Katwa) : You should give your ruling about the expunction, Sir.

SHRI RANJEET SINGH : It may be bad, but it does not require expunction.

MR. CHAIRMAN : There is nothing which needs to be expunged.

श्री जनेश्वर मिश्र : सभापति महोदय, मैं जान-बूझ कर यह बता रहा था कि उत्तर प्रदेश में जो लोग राजनेता हैं, और जो खासकर ताकत की राजनीति करते हैं, वे भाई-भतीजावाद के चक्कर में इतना फंस गये हैं कि प्रदेश की प्रगति रुक गई है।

जब मैंने प्रधान मंत्री का नाम लिया है, तो अब भी मैं यह कहना चाहता हूं कि अगर उत्तर प्रदेश से प्रधान मंत्री का ओहदा नहीं हटाया गया, तो उत्तर प्रदेश की तरक्की नहीं होने वाली है। उत्तर प्रदेश की तरक्की के लिए यह जरूरी हो गया है कि प्रधान मंत्री बिहार का बने, या तामिलनाडू का, या हरियाणा के चौधरी रणधीर सिंह बनें। (**व्यवधान**) उत्तर प्रदेश में जो लोग बहुत दिनों से राजनीति में रहे हैं, उनका दिमाग थोड़ा सामन्ती होता है, वे खर्चीले दिमाग के होते हैं। जब श्री चन्द्रभानु गुप्त उत्तर प्रदेश के मुख्य मंत्री थे, तो श्रीमती इंदिरा गांधी ने उत्तर प्रदेश का दस दिन का दौरा किया। इस बारे में श्री चन्द्रभान गुप्त ने एक बयान में कहा कि दस दिन के दौरे पर चार लाख रुपये खर्च हुए। एक दिन में चालीस हजार रुपये पड़ते हैं। यह कोई मामूली रकम नहीं है। हम तो यहां तक कहने के लिए तैयार हैं कि अगर उत्तर प्रदेश से प्रधान मंत्री का दौरा खत्म कर दिया जाये, तो उत्तर प्रदेश में नहरें, सड़कें और ट्यूबवैल बन जायेंगे। चालीस रुपये में दो ट्यूबवैल बनते हैं। चालीस हजार रु० में बीस बीघे का खेत खरीदा जाता है। चौधरी साहब फिर कहेंगे कि मैंने कोई असंसदीय बात कही है, लेकिन अगर हम कहें कि प्रधान मंत्री रोज बीस बीघा खेत चर जाती हैं, तो क्या हम कोई गलती करेंगे—वह रोज दो ट्यूबवैल का पानी साफ कर जाती हैं, तो क्या उसमें कोई गलती होगी ? हम उन की इज्जत करते हैं, लेकिन यह फिजूलखर्ची क्यों ?

यहां पर मेजर रणजीत सिंह बैठे हुए हैं। इनके यहां बस्ती जिले के कलेक्टर की कोठी पचास बीघे में बन रही है, जहां एक मोटर-गेराज लेने के लिए बीस रुपया महीना किराया दिया जाता है। फिजूलखर्ची नीचे से लेकर ऊपर तक, उत्तर प्रदेश की नौकरशाही से ले कर हिन्दुस्तान के प्रधान मंत्री तक, फैली हुई है।

अगर यह संसद् उत्तर प्रदेश की तरक्की कराना चाहती है, तो वह मेहरबानी कर के प्रधान मंत्री का पद किसी दूसरे सूबे में दे दे, ताकि कमल भी दूसरे सूबे में चला जाये और उसके साथ जो कीचड़ रहता है, जो गन्दगी और गरीबी रहती है, वह भी किसी दूसरे सूबे में चली जाये।

जब पहली मर्तबा अंग्रेज यहां आया, तो वह बम्बई, कलकत्ता और मद्रास के समुद्री किनारे पर उतरा। उतरने के साथ-साथ उसने उन इलाकों के लोगों की तरक्की के लिए रास्ता बनाया। इस तरह उन लोगों को अपनी

[श्री जनेश्वर मिश्र]

तरक्की का चस्का लग गया। बेचारे इन मध्य प्रदेश वालों को, चाहे वे उत्तर प्रदेश के हों या मध्य प्रदेश या राजस्थान के, तरक्की का चस्का नहीं लगा। आजादी मिलने के बाद भी उन्हें तरक्की का चस्का दिखाने की जगह ओहदे का चस्का दिखा दिया गया। और राजनीति में जिसको ओहदे का रोग हो जाता है, वह अपनी जनता की तरक्की नहीं किया करता है। इसलिए मैं इस सदन से बार-बार कहूंगा कि उत्तर प्रदेश की तरक्की के लिए, वहां पर बढ़िया समाजवाद स्थापित करने के लिए, वहां की गरीबी को खत्म करने के लिये और एक बेहतर जिन्दगी देने के लिए यह बहुत जरूरी है कि उत्तर प्रदेश से प्रधान मंत्री के ओहदे को खत्म कर दिया जाये।

मैं उत्तर प्रदेश की सरकार और जनता से भी कहूंगा कि अगर उत्तर प्रदेश की तरक्की में दिल्ली बाधक रहा है—अगर उसने सूखे, अकाल, बाढ़ और बरसात के सवाल को लेकर उत्तर प्रदेश को पूरा पैसा नहीं दिया है; यह सवाल हमेशा उठाया गया है कि किसी दूसरे सूबे को 14 करोड़ रुपया दिया गया है, तो उत्तर प्रदेश को डेढ़ करोड़ रु० यह बहस कई बार छिड़ी है। उन दूसरे सूबे वालों से हम को जलन नहीं है। उन्हें 14 की जगह 20 करोड़ मिल जाय, हम खुश होंगे। वह भी हमारे देश के हिस्से हैं। लेकिन हम इतना जरूर कहेंगे कि केवल राजनैतिक दबाव में आ कर ऐसा किया जाय यह ठीक नहीं है और उत्तर प्रदेश के लोग अपनी दिल्ली की गद्दी बचाने के लिए उत्तर प्रदेश की तरक्की को नजरअन्दाज करते हैं तो उत्तर प्रदेश की जनता और उत्तर प्रदेश की गैर-कांग्रेसी सरकार उत्तर प्रदेश की तरक्की के लिए और कोई मंसूबा बनाए और दिल्ली की सरकार कोई मदद नहीं करती है तो ऐसा रास्ता तय करे कि किस तरह से दिल्ली की सरकार को ठीक किया जा सकता है।

श्री क० ना० तिवारी: सभापति महोदय, यह जो जिले या देश के हिस्से पिछड़े हुए हैं उसकी चर्चा हम लोग कर रहे हैं। यह ठीक कहा किसी ने कि अच्छा होता कि वित्त मंत्री यहाँ रहते क्योंकि यह वित्त से सम्बन्ध रखता है उत्तर प्रदेश के पूर्वी हिस्से के बारे में जो बात कही गई वह हमारा पड़ोसी प्रान्त है और हमार जिले से वह लगा हुआ है। करीब-करीब वही हालत हमारे उत्तर बिहार की भी है। बिहार दो हिस्सों में बटा है—उत्तर और दक्षिण। हम उत्तर बिहार से आते हैं। उत्तर बिहार की भी करीब-करीब वही हालत है। हमारे यहां कोई इंडस्ट्री नहीं। सिवाय चीनी के उद्योग को छोड़ कर छोटे उद्योग भी हमारे यहां नहीं हैं। बड़ा उद्योग केवल एक बरौनी में है और दूसरी जगह नहीं है। इसलिए हमारे यहां से मांग हुई उत्तर बिहार से कि हमारा अलग डेवलपमेंट बोर्ड बनाया जाय। वहां से सभी पार्टियों के चाहे वह कम्युनिस्ट पार्टी हो, एस० एस०पी० हो, कांग्रेस हो सभी के नेताओं ने मिल कर के एक मेमोरेंडम दिया सेन्ट्रल गवर्नमेंट को और वह सभा के पटल पर भी रखा गया। लेकिन आज तक वहां डेवलपमेंट बोर्ड नहीं बना। हम एक निवेदन करना चाहते हैं सरकार से कि वह बिहार सरकार को आदेश दे कि समय रहते बिहार गवर्नमेंट वहां डेवलपमेंट बोर्ड बनाए। यह बात कही जाती है कि बिहार में बड़े-बड़े उद्योग जैसे बोकारो है, हटिया है इसमें काफी पूंजी सरकार की लगी हुई है। बात सही है लेकिन इससे जो फायदा होना चाहिए बिहार को वह नहीं हो रहा है, उसका पिछड़ापन दूर नहीं हो रहा है। वह चूंकि दो हिस्सों में है, गंगा बीच में उसको बाँट देती है—उत्तरी भाग और दक्षिणी भाग, तो उत्तरी भाग जो केवल कृषि-प्रधान रह गया है और वहाँ कोई उद्योग नहीं है इस वजह से हर दृष्टि से वह पिछड़ा हुआ है और जब तक वहां उद्योग नहीं बढ़ेंगे तब तक वहां का पिछड़ापन नहीं जायगा। इस पचड़े में मैं नहीं जाना चाहता कि लोगों

को रोजगार कैसे मिलेगा या पिछड़ापन कैसे दूर होगा। लेकिन मेरी अपनी धारणा है कि पिछड़ापन किसी भी देश का या देश के किसी भी भाग का तब तक नहीं दूर होगा जब तक वहां इंडस्ट्री नहीं बढ़े, तब तक वहां की आर्थिक स्थिति में कोई सुधार नहीं होता। केवल जमीन के ऊपर बोझ लादते जाना और उसी से समझ लेना कि हम जमीन का बटवार कर देंगे तो हमारा पिछड़ापन दूर हो जायगा, अगर यह बात होती तो हम समझते हैं कि जो हालत आज हमारे देश की है वह करीब पचास या सौ वर्ष पहले अमेरिका की थी और इतना ही दबाव वहां जमीन पर था। लेकिन जब इंडस्ट्री बढ़ी तो दबाव जमीन पर छः परसेन्ट रह गया और बाकी सभी लोगों को एम्प्लायमेंट मिला, वह लोग इंडस्ट्री में चले गए। इस तरह से देश के बहुत से हिस्से हैं जहां पिछड़ापन है। बराबर डेवलपमेंट हमारा नहीं हुआ है। बहुत ही ऊबड़खाबड़ ऊंचा नीचा डेवलपमेंट हुआ है और इसकी वजह सब से बड़ी यह है कि हमारा प्लानिंग इतना डिफेक्टिव है, मिसाल के लिए मैं एक बात कह दूं, प्लानिंग कमीशन के साथ हमेशा यह सवाल उठता रहता है कि हमारे शहरों के अन्दर जो बहुत खराब हिस्से हैं, स्लम एरिया है, उसको खत्म करना चाहिये, झुग्गी-झौपड़ी का सवाल उठता है, लेबर का सवाल उठता है, लेकिन देहाती क्षेत्र के लिये—यह सरकार जो इस बात की हामी भरती है कि हम गांधी जी के रास्ते पर चलते हैं और गांधी जी हमेशा इस बात को कहते थे कि हिन्दुस्तान की आत्मा देहातों में रहती है—देहाती क्षेत्रों के स्लम के लिये क्या आप कभी विचार करते हैं ? मैं पूछना चाहता हूं कि देहातों में स्लम एरियाज कितने हैं। नन्दिनी सत्पथी जी उड़ीसा से आती हैं, उड़ीसा की हालत भी पिछड़ेपन में वैसी ही है, जैसी बिहार और ईस्टर्न यू०पी० की है, इस लिये मैं जानना चाहता हूं कि इन क्षेत्रों के स्लम एरियाज के इम्प्रूवमेंट के लिये आप क्या कर रहे हैं ? आज जो रुपया राज्यों को देहाती क्षेत्रों के लिये दिया जाता है, वह उनके जनरल बजट में चला जाता है। चीफ मिनिस्टर्ज कहते हैं कि हम इस को उनके डेवलपमेंट के लिये ईयर-मार्क नहीं करेंगे, हम जैसे चाहेंगे वैसे खर्च करेंगे—इस तरह से बात नहीं चल सकती। में इस गवर्नमेंट को आगाह करना चाहता हूं—अगर आप उस हालत से बचना चाहते हैं जो आज बंगाल में पैदा हो रही है, अन्य प्रान्तों में पैदा हो रही है, तो आप इस बात को समझ लीजिये कि अगर आप ने हर हिस्से का डेवेलपमेंट नहीं किया, इंडस्ट्रीज नहीं बढ़ाई, लेबर अनरेस्ट और लेबर आर्गेनिजेशन्ज से डरते रहे, किसानों से नहीं डरे तो देख लीजिये सामने दीवार पर क्या लिखा है। आज यहां जितने लोग आते हैं, उनमें सब से बड़ी संख्या देहातों से आनेवालों की है, अगर आपने देहात के मसले को हल करना शुरू नहीं किया, उस पर विचार करना शुरू नहीं किया, तो आज जिस परिस्थिति में आप हैं, उस परिस्थिति में नहीं रह सकेंगे।

अन्त में एक बात कह कर समाप्त करूंगा। मेरा जिला चम्पारन है, वहां पर गण्डक योजना चल रही है, अगर उसको ही आप पूरा कर दें तो हमारे यहां की पैदावार 29 लाख टन हो जायगी, जिससे बिहार का जो 12 लाख टन का डैफिसिट है, वह पूरा हो जायगा, और हम सरप्लस स्टेट हो जायेंगे, सारे बिहार को खिला-येंगे और दूसरे जो डैफिसिट एरियाज हैं उनको भेज सकेंगे। इसलिये मेरा अनुरोध है कि उस को जल्द पूरा कराने की कृपा कीजिये, जिससे कई लाख एकड़ जमीन पटेगी और खेती की पैदावार बढ़ेगी।

SHRI G. KUCHELAR (Vellore) : I thank you for the opportunity given to me to take part in this debate.

I have to say that there is only one district in my State, Tamil Nadu, that has been included in the list approved by the Centre while there are about four districts which are very backward and need development badly. These are Tirunelveli, Ramnad, Dharmapuri and North Arcot districts. No action is being taken either by the State or the Centre to initiate any

[Shri *G.* Kuchelar]

development schemes there either through the BDO organisation or the Panchayats etc. Because of paucity of funds, we are unable to meet the expenditure for the purpose of developing these backward areas.

In Tirunelveli, there are no irrigation facilities. There has been a proposal or project called the Ohenakal project which was sponsored since the days when the British were here. But it has not been taken up even later on by the then ruling party there namely, the present Congress(0). Thus this area remains neglected. Not even a single part of these districts has been taken up for development.

The people of Tirunelveli District have to go to Madras or some other nearby district for their daily livelihood, and they have even come to Delhi to do house-hold work here. This shows how deplorable their condition is. Similarly, in the Dharmapuri area there is neither any industry nor irrigation. So, the people are hard put to it as they cannot find any means of livelihood. In my own District of North Arcot, there is a river called Palaru which means a river yielding milk. It is only in name. There is no milk, nor even any water available in the area. Of course we get a lot of sand, but that is also of no use. Hence, no proper cultivation is possible in the entire district. Many Dam works like 'Marethana' Bandanapalli, Melpath in North Arcot district are pending in the state for want of funds.

The State Government has submitted a scheme to the Centre for a sub-soil water reservoir and requested sufficient funds for the same, but I do not know whether it has been considered by the Centre so far.

I give my appreciation and thanks to the Central Government for having considered a small scheme of survey costing Rs. 45 lakhs in North Arcot, Chingleput and Tanjore Districts. I have, however, to point out that the entire State of Tamil Nadu has to depend upon the paddy produced in Tanjore District alone, because there are no irrigation facilities available in the other districts nor industrial development.

In order to raise funds for development purposes, a lottery ticket scheme was sponsored by our late Anna, the former Chief Minister. It has been going on regularly without complaints and the money is being used for development of our State, but I am surprised to note that the Railway Minister, Nandaji is opposing the sale of these tickets at Railway Stations. If co-operation is not extended by the Centre to the State over such a small matter, I wonder how the State development schemes can be implemented successfully. The great saint Tiruvalluvar has said :

'Eattalum Kattalum vahuttalum vahuttapin Aatralumy valladu arasu.'

That means that only that Government will earn a good name which knows how to tap the resources, divide them equally among the various sections of the people and spend the money properly for the benefit of the people.

I hope that the Central Government would extend their financial help to the Tamil Nadu State for implementing schemes which will benefit such backward areas.

श्री झारखण्डे राय (घोसी) : माननीय, समस्त विश्व में जितने उन्नत देश हैं उनमें भारत ही एक पिछड़ा हुआ देश है । भारतवर्ष के सब से प्रमुख पिछड़े प्रदेशों में उत्तर प्रदेश की भी गिनती है । हमारे देश के 58 पिछड़े जिलों में से यू०पी० के 22 जिले हैं जिनमें उत्तर प्रदेश के पूर्वांचल के ही 14 जिले हैं । यह हमारी स्थिति है । इसका पिछड़ पन इसी तथ्य से प्रकट हो जाता है कि राज्य में कोई विकसित जिला नहीं है । कोई भी ऐसा जिला नहीं है जिसको कि विकसित कहा जा सके ।

हमारे उत्तर प्रदेश के तीन प्रमुख क्षेत्र हैं जोकि पिछड़े कहे जाते हैं, पूर्वांचल, बुन्देलखंड

और पर्वतीय क्षेत्र । मैं अपने सुझावों द्वारा ही अपनी बात रखना चाहूंगा । पूर्वांचल के 14 जिले और बिहार के पश्चिमांचल के कुछ जिलों को मिला कर वह एक प्रदेश बनाया जाय । अब हमें इस बात का विश्वास नहीं है कि मौजूदा हालत रहते हुए और उसकी पोषक सरकार के रहते हुए हमारे पूर्वांचल का समुचित विकास हो सकता है । इसके लिए जरूरी है कि समस्त हिन्दी भाषा भाषी भारत के पुनर्विभाजन के लिए एक दूसरा पुनर्समिन आयोग स्थापित कीजिये ।

जितनी भी परती जमीन है वह सारी बंजर जमीन चाहे वह जंगल की जमीन के नाम पर खाली पड़ी जमीन हो और साथ ही बड़े-बड़े फार्मों को जब्त करके सब जमीन भूमिहीनों और हरिजनों में बांटी जाय ।

आजमगढ़ गाजीपुर, बलिया, जौनपुर के क्षेत्र में चीनी मिलें और पूरे अंचल में हड्डी, शीशा, चमड़ा आदि के बड़े उद्योग पब्लिक सैक्टर में खोले जायं ।

हैंडलूम और पावरलूम जो वहां के परम्परागत उद्योग रहे हैं उनके विकास के लिए समुचित कार्यवाही की जाय और उनको पूंजीपतियों की चोट से बचाया जाय ।

नारायणी–सरयू–राप्ती की बृहद नदी घाटी योजना बनाई जाय जिससे पूर्वांचल में विद्युत और नहरों का जाल बिछाया जा सके । केवल इसी तरह पूर्वांचल का विकास हो सकता और इसके अलावा और कोई रास्ता नहीं है ।

बाढ़ नियंत्रण योजना प्रभावी ढंग से लागू की जाय । बाढ़ क्षेत्र के सभी गांवों की सतह ऊंची की जाय । बाढ़ के कारण जो गांव बह जाते हैं तो उन गांवों की सतह को ऊंचा करने का काम जो अधूरा पड़ा हो उसे तत्काल पूरा किया जाय ।

तीन योजनाओं के बाद भी देश में सड़कों का जाल बिछाने का काम पूरा नहीं हो पाया है इसलिए यह सड़कों का जाल पूर्वांचल में बिछाया जाय ।

विशाल जलमाण्डम् (रिजरवायर) के निर्माण हों तथा बरसाती पानी को रोक कर उसे उपयोगी काम में लाया जाय ।

पूर्वोत्तर रेलवे का डिवीजनल हेडक्वार्टर गोंडा में ही रहना चाहिए । वह जो गोंडा में उसका स्थानांतरण कर दिया गया है उसे रोका जाय । यह गांधीवादी विकेन्द्रीकरण के सिद्धान्त के भी खिलाफ है ।

पूर्वांचल के बड़े केन्द्रों को बड़ी लाइन से जोड़ना चाहिये । गाजीपुर में भी गंगा पर पुल बने, केवल बक्सर पुल से काम नहीं चलेगा । मिरजापुर–चकिया और बिहार के सटे भूखंड में पृथ्वी के गर्भ में छिपे अकूत खनिज भंडार का उपयोग किया जाय । विशेष क्षेत्रों में लिफ्ट इर्रीगेशन की व्यवस्था हो । सभी गांवों को बिजली दी जाय । तीनों पिछड़े अंचलों के लिए तत्काल स्वायत्तापूर्ण विकास बोर्ड बनाये जायं । एक अरब की आय के लिये सारे देश को शराबी तो गाँधी का नाम लेने वाले शासकों ने बना ही दिया । अब लाटरी की पद्धति को चला कर सारी जनता को जूआरी बनाया जा रहा है । द्यूत विद्या को राज–प्रश्रय महाभारत काल में प्राप्त था और इस लाटरी की प्रथा को चला कर कांग्रेस काल में पुनः प्राप्त हुआ है । यह इतिहास की पुनरावृत्ति हो रही है । यह शराब और लाटरी दोनों ही बंद की जायं । पूरी शराबबंदी लागू हो और लाटरी बंद हो ।

साधनों के संकट के नाम पर पूर्वांचल का विकास अब नहीं रोका जा सकता है ।

चौथी पंचवर्षीय योजना में 27 अरब के नये टैक्स लगेंगे । इससे अधिक ही होगा । फिर भी 20 अरब की कमी रह जायेगी । उसके लिए नये टैक्स लगाने और राष्ट्रीयकरण करना यह दो ही मार्ग हैं । मैं बलपूर्वक कहूंगा कि अब सभी मुख्य एवं बुनियादी देशी

[श्री झारखण्डे राय]

एवं विदेशी दोनों प्रकार के उद्योगों के राष्ट्रीयकरण की ओर आगे बढ़ा जाय क्योंकि टैक्सेस का बोझ बढ़ाना मौत की घाटी का रास्ता है और राष्ट्रीयकरण जिंदगी की राह है। अलबत्ता यह हमें ध्यान रखना होगा कि सांप को छेड़ा जाय तो फिर उसे छोड़ा न जाय वरना वह पूंजीपति सरकार को भी खा जायेंगे और साथ ही देश की जनता को भी। किफायतशारी उत्तरोत्तर की जाये। इसके लिये पहला उपाय यह है कि जो एक अरब रुपये का अय्याशी का सामान विदेशों से आता है वह फौरन एक कलम की नोक से बन्द किया जाये। इन उपायों से ही हम पूर्वांचल के विकास का काम कर सकते हैं, इनके सिवा और कोई रास्ता नहीं है।

पूर्वांचल के प्रति और उत्तर प्रदेश के प्रति भी केन्द्र और राज्य सरकार दोनों ही जिम्मेदार हैं। हम एक पर जिम्मेदारी डाल कर दूसरे को बचा नहीं सकते। 1967 तक सभी एकाधिकार पूरी कांग्रेस पार्टी का था, कोई दूसरा उसका भागीदार नहीं था। इसलिये दोनों ही जिम्मेदार हैं इस पिछड़ेपन के लिये, केन्द्र और राज्य सरकार, चाहे वह पूर्वांचल हो या पूरा उत्तर प्रदेश हो। पूर्वांचल के प्रति और उत्तर प्रदेश के प्रति केन्द्र का हमेशा से एक सौतेला—सा व्यवहार रहा है। मैं यह शिकायत बहुत जोरदार तरीके से करना चाहता हूं। हो सकता हैं कि चूंकि प्रधान मंत्री हमेशा उत्तर प्रदेश से ही आते रहे इसलिये उन्हें यह भय रहा हो कि कहीं कोई हम पर पक्षपात का चार्ज न लगा दे। इसी चार्ज के डर से शायद उत्तर प्रदेश को उसका उचित भाग नहीं दिया गया और इस प्रकार का व्यवहार किया गया।

उत्तर प्रदेश के पिछड़ेपन के पीछे सदैव कुछ न कुछ कारण रहा है। अंग्रेजों ने इस लिये उत्तर प्रदेश की उपेक्षा की कि वह शाश्वत विद्रोही क्षेत्र रहा है। बाबू कुंवर सिंह राजा देवीवख्श सिंह आदि ने गोगा साहु के नेतृत्व में 1957 में अंग्रेजों को अपनी शमशीर का पानी चखाया था। 1942 के विद्रोह में उसके पूर्वांचल अधिकांश भाग से अंग्रेजी राज्य समाप्त हो गया था और अंग्रेजों को उसको रिकांकर करना पड़ा। अंग्रेजों की यह उपेक्षा तो समझ में आ सकती है, लेकिन जो कांग्रेस सरकार उपेक्षा कर रही है उसका एक ही कारण हो सकता है कि 1947 के बाद भी वह क्षेत्र मजदूर और किसान आन्दोलन का क्रांतिकारी केन्द्र रहा है। इस वजह से इस सरकार ने भी उस की उपेक्षा की है। मैं कहना चाहता हूं कि अगर पूर्वांचल और बुन्देलखंड का विकास नहीं होगा तो उसके अन्दर एक जबर्दस्त असन्तोष की आग सुलग रही है और वह बढ़ती जायगी।

पूर्वांचल की इस धरती को बंगाल बना कर छोड़ेंगे।

बुन्देलों की धरती को बंगाल बनाकर दम लेंगे।

हिमगिरि की इस धरती को बंगाल बना कर मानेंगे।

आज यह नारा चलता है, टकराता है पहाड़ों से, मैदानों और जंगलों से। इसका कोई मतलब होता है। मैं चाहता हूं कि पूर्वांचल के कांग्रेसी शासक समय रहते चेतें। अगर वहां जन-विद्रोह जगेगा तो उसका उनको समाधान करना पड़ेगा। वह उसका समाधान करें तभी उनका कल्याण है, देश का कल्याण है और पूर्वांचल का भी कल्याण हो सकता है।

श्री नागेश्वर द्विवेदी (मछली शहर) : सभापति महोदय, आपने इस महत्वपूर्ण विषय पर मुझ को कुछ कहने का अवसर दिया, इसके लिये मैं आपके प्रति आभार प्रकट करता हूं।

जैसी मुझ से पूर्व वक्ताओं ने चर्चा की, देश के सब से पिछड़े हुए जिले इसी जगह है। पूर्वी उत्तर प्रदेश की आर्थिक स्थिति के बारे में समय

समय पर बार-बार चर्चा की जाती है। उसके बारे में पटेल आयोग ने जो सिफारिशें की थीं वह शुरू भी नहीं हो पाई थीं कि चीनी आक्रमण के बाद उनका काम रोक दिया गया। फिर जब पाकिस्तानी आक्रमण हुआ तब भी उनको रोक दिया गया। हम लोगों ने आशा की थी कि अब जब शांति का समय आया है और सुरक्षा की स्थिति पैदा हुई है और पंच-वर्षीय योजना पर फिर से विचार हो रहा है तब पूर्वी उत्तर प्रदेश का खास खयाल रक्खा जायेगा। लेकिन हम देख रहे हैं कि उसकी तरफ उसी तरह से उपेक्षापूर्ण दृष्टि रक्खी जा रही है। आज आर्थिक दृष्टि से उत्तरोत्तर पूर्वी उत्तर प्रदेश गिरता चला जा रहा है, जैसा आंकड़ों से सिद्ध किया गया है। हम को बहुत से आश्वासन दिये जाते हैं, समय-समय पर बहुत सी बातें कही जाती हैं, बहुत से नेता लोग इस तरह की बातें कहते हैं कि यह राम और कृष्ण की लीला भूमि रही है, तुलसी और कबीर की जन्मभूमि रही है, लेकिन इन आश्वासनों से हम ज्यादा दिन तक संतोष नहीं कर सकते हैं आखिर वहां के लोग भी आदमी हैं, वहां के लोग भी सुख और आराम उठाना चाहते हैं। वहां की आर्थिक स्थिति को देखते हुए सरकार और कुछ न कर सके तो कम से कम इतना तो करे कि वहां यातायात की सुविधा दे और बिजली की सुविधा पैदा कर दे। बाकी लोग किसी न किसी तरह से कोई न कोई उपाय करके अपनी जीविका के लिए साधन जुटा लेंगें। वहां गांवों में न तो बिजली जाने पाती हैं और न सरकारी नल कूप लगाए जाते हैं। अगर लोग, प्रयास करके अपने पम्पिंग सैट लगाना चाहते हैं और उनके लिए एप्लीकेशन देते हैं तो देखा गया है कि उनकी एप्लीकेशंज साल-साल और दो दो साल तक पड़ी रहती हैं और उनको बिजली का कनेक्शन नहीं मिल पाता है।

सभापति महोदय, सरयू और जमना के बीच का क्षेत्र वह क्षेत्र हैं जोकि हिन्दुस्तान का सबसे बड़ा उर्वर क्षेत्र हुआ करता था जोकि हर तरह से सम्पन्न और खुशहाल था और जहां के लोगों को खाने पीने के लिए बहुतायत से मिल जाया करता था। यह वह क्षेत्र था जहां लोग जाना और जा कर बसना चाहते थे। अब वही क्षेत्र दरिद्रता में अपना जीवन व्यतीत करें, वहां के लोग दैन्य पूर्ण जीवन व्यतीत करे, लोगों के सामने जा कर अपना दुखड़ा रोयें, यह अच्छा नहीं लगता है। जब सरकार विकास के नाम पर, लोगों की तरक्की करने के नाम पर, पिछड़े क्षेत्रों के उत्थान के नाम पर सारे काम करती है और उसके लिए टैक्स वसूल करती है और इस तरह के आश्वासन देती है कि योजना बना कर उनका उत्थान किया जाएगा, तो वहां के लोगों की भी इच्छा होती है कि वे अपनी बात सरकार के कानों तक पहुंचायें और इस बात की कोशिश करें कि वे भी दूसरे लोगों के साथ कदम से कदम मिला कर आगे बढ़ें और इसमें सरकार उनकी सहायता करे।

मैं कहना चाहता हूं कि सचमुच में अगर सरकार इसी तरह से उस क्षेत्र की उपेक्षा करती रही और इसी तरह से उस क्षेत्र की उपेक्षा होती रही तो हम लोगों को बाध्य हो कर कहना पड़ेगा कि जैसे आप छोटे-छोटे प्रांत बनाते जा रहे हैं और बना चुके हैं, वैसे ही आप उत्तर प्रदेश को तीन या चार टुकड़ों में बांट करके उसके तीन चार प्रांत बना दें। हर एक प्रांत में तेरह-तेरह जिले होंगे जोकि बहुत से अन्य प्रांतों से दुगने और तिगुने बड़े होंगे। अगर यही हालत चलती रही तो उत्तर प्रदेश के लोग इस बात को सोचने के लिए मजबूर होंगे कि उत्तर प्रदेश के भी टुकड़े कर दिये जायें, आर्थिक दृष्टि से छोटे-छोटे टुकड़े कर दिए जाएं और उनको पिछड़ा हुआ गिना जाने लगे और वे खुद अपनी मदद करें और सरकार भी उसमें अपना सहयोग उनको प्रदान करे। आज जो स्थिति है उसमें पूर्वी उत्तर प्रदेश के लोग खास तौर पर और उत्तर प्रदेश के लोग आम तौर पर बहुत दुखी हैं। इसका लांछन वे चाहे केन्द्रीय सरकार पर लगायें या प्रांतीय सरकार पर और चाहे इसका लांछन वहां के लोगों की आपसी लड़ाई पर लगाया जाए, लेकिन यह बात अपनी

[श्री नागेश्वर द्विवेदी]

जगह पर रही है कि वह क्षेत्र पिछड़ा हुआ है और उसके पिछड़ेपन को दूर करने का प्रयास किया जाना चाहिये, उसको आगे लाने का प्रयास किया जाना चाहिये ।

SHRI UMANATH : Sir, I join in the sentiments expressed by various members about the backwardness of eastern UP. In January, 1964, a report was submitted by the Planning Commission's team which went into the position of eastern UP. They made a specific recommendation that the responsibility for the development of the backward areas in all the States must lie primiarly with the Central Government as well as the State Government concerned. After that, Government had gone on record here that they accept the recommendations of this team. That report gave a concrete programme in all sectors so far as four districts of eastern U. P. are concerned. They said, for accelerated development within the end of the third plan, Rs. 10.49 crores must be allotted and in the fourth plan, they proposed Rs. 74.64 crores for the four districts only. They gave details about industry, agriculture, etc. When the minister replies, she should categorically say what Government have done with regard to the recommendations which they themselves said they have accepted, not only in terms of money but also in terms of progress made in these districts sector-wise *vis-a-vis* targets laid down in that report. It is better they open their eyes at least at this stage, because the toiling people of eastern UP have started opening their eyes. They are now determined to refuse to be chattels whose loyalty for the Nehru family in U. P. was exploited for getting votes, for forming the government and for becoming MPs. That position has gone.

Take the general attitude of Government with regard to backwardness in the country, it is one of evading the issues in practice, all the while giving assurances, raising hopes in the minds of people in backward pockets and deceiving them.

I will give you one example. There is the question of indicators, the criteria for determining backward areas. In August 1962 the Planning Commission sent a circular to various State Governments, giving them the criteria on the basis of which they must identify the backward areas. After one year, on 29.9.64 Shri Bhagat, then then Planning Minister, informed the House ;

> "Earlier they (State Governments) were asked to give information ; as I said, it was full of gaps and the areas selected were not on scientific basis. So, after this report (Eastern U. P. Report), the Planning Commission have selected 15 indicators like density of population ....etc. So, each Government is asked to identify the area on the basis of these selected agreed indicators."

You will find from that they have now decided the indicators, criteria, everything. After four years they say:

> "At the meeting of the Committee of the National Development Council on September 10, 1968 it was decided that two working groups should be set up. In pursuance of the decision, two working groups have been set up by the Planning Commission. One working group was to recommend the criteria for identifying the backwardness."

Already, in 1962 one circular went round. Later on, the report of the Planning Commission came where they said that on a scientific basis they have decided on 15 indicators. After five years they say that the National Development Council Working Group should select the indicators.

Finally, I will give my own experience about the attitude of the government towards development of backward areas. One of the backward areas in Tamilnadu, apart from those mentioned by my hon. friend of the DMK, is Pudukottah-Ramnad-Arantangi. I come from Pudukottah area. On 12.6.62 when this question was raised in the Lok Sabha there was no reply. On 7.9.62 a memorandum was sent to Shri Nanda, the then Planning

Minister. There was no reply. On 10.12.63 during the Mid-term Appraisal of the Third Plan. I raised this issue again. While replying to that, Shri Bhagat said :

> "Very soon the report of this team will be out and then that will give us a pattern which we can apply to all these areas, so that the district of the hon. Member will also be covered, as also the area of Pudukkottai. The hon. Member from that place spoke with great feelling and he even threatened the government with mass action. I think all his fears are misplaced. Once the pattern is settled, I think in the coming two years or in the next plan we will do something."

This was his promise. After the report was published I asked the minister on the floor of the House whether the State Government have identified the areas. The then Minister, Shri Asoka Mehta said : Yes, the Tamilnadu Government have identified 19 districts as backward areas. Then I asked what he proposed doing in respect of these areas. Shri Asoka Mehta replied on behalf of the Government of India ' it is none of our business ; it is the business of the State Government."

Then there was a half-an-hour discussion in which this question was raised. In reply to a question on 17.9.64 it was stated :

> "The pattern of development of backward areas in different States will have to be based on studies of the economic and social condition of these areas."

Earlier we were told that as soon as the report is submitted with regard to the pattern, we will do something. When the report was submitted we asked : what are you going to do ? Then they say that they will get the pattern after a socio-economic study. This is how they have been dealing with this question.

In 1967 Shri Asoka Mehta, the then Minister said that 19 districts have been selected in Tamilnadu. When I asked what they are doing about them he said : it is none of our business. Then I approached the Prime Minister and said that an assurance has been given on the floor of the House which has been violated. Then the hon. Prime Minister, Shrimati Indira Gandhi, wrote to me a letter in which she said : we have decided in the Chief Ministers' Conference that ten per cent of the Five Year Plan funds will be kept separately for special problems of the various States, the State Governments can spend for the development of backward areas out of this ten per cent and you can approach the State Government in the matter. Then I approached the Chief Minister of Tamilnadu, Shri Karunanidhi and showed him the letter of the Prime Minister and asked him : is this a fact, is this the position ? It is more than a year since I wrote to the Chief Minister and to this day there has been no reply.

The state of affairs has come to this that just to get a reply from the Chief Minister I, a Member of this House had to write three reminders and send them by registered post. His private secretary signed the registered post acknowledgement, but on this question no reply is being given. I think, the only course will be that either I will have to go on a hunger strike before the Chief Minister's house just to get a reply to a communication from an hon. Member of this House or I shall have to bring up a privilege motion against the Chief Minister of Tamil Nadu on this question, because my work in the constituency is being obstructed because of the attitude of the Chief Minister. The Prime Minister shunts us to the Chief Minister and the Chief Minister keeps quiet ? This is the position.

Between the united Congress, then the divided Congress and now the seemingly united DMK, Pudukkottai and that entire area is today as it was in 1947 when the merger took place. Similar is the position in all the backward areas of all the States. If these backward area people become frustrated and get angry and in certain areas take to arms in desperation....as my hon. friend said earlier, that is the slogan in the various hills....what is the use of blaming those

[Shri Umanath]

people or the parties when the Government deliberately for the past 25 years has been betraying these people for nothing ?

It is not for nothing that there is this attitude of the Government. It is the attitude of the big business. When they want to establish industries, their concern is which is the place where they will get the maximum profit. It is the same attitude that is reflected by this Government; otherwise, these things would not have happened. If this thing continues, I warn the Government that we do not want any more sentiments of sympathy from the hon. Minister. After all the reports recommendations and assurances on the floor of the House, now we want the Government to state clearly how much advance has been made; if not, why it has not been made and what they are going to do actually, otherwise things will take a serious turn and we will stand by the people if the people take to a struggle and militant action against the Government's policy to defeat their policy so that they can advance.

SHRI K. LAKKAPPA (Tumkur) : Sir, the hon. Member, who has brought up this discussion about the economically backward regions in the country particularly in Uttar Pradesh, has to be congratulated. It is not the question of Uttar Pradesh alone being economically backward but particular regions in several States are equally more backward.

The Planning Commission that is working now is a big white elephant. It is the congregation of ICS and IAS officers. They are planning in such a way that it will all go to the pockets of big business houses. My hon. friend has just now said where industries are located.

I would like to quote the figures of *per capita* income of various States in India as quoted by the Prime Minister in an answer on 1st April, 1970. According to the statement laid on the Table of the House, the *per capita* income is: Andhra Pradesh—Rs. 438; Assam—Rs. 441; Bihar—Rs. 299; Gujarat—Rs. 523; Haryana—Rs. 504; Jammu and Kashmir—Rs. 341; Kerala—Rs. 393; Madhya Pradesh—Rs. 373; Maharashtra—Rs. 526; Mysore—Rs. 420; Nagaland—nil; Orissa—Rs. 347; Punjab—Rs. 575; Rajasthan—Rs. 356 and so on. From the statistics given by the hon. Prime Minister we can see how the Finance Ministry has been working for the last 20 years. Money has been going only to States which are developed and which have a higher *per capita* income, like Maharashtra and Gujarat. The southern States have been neglected throughout and even their *per capita* income has gone down. Bihar also there which has been completely neglected. Therefore, all these politicians have committed a fraud on the Constitution, on the guarantees given under the Constitution, and the southern State have been completely neglected. They have used all the money, all the economic resources, for the development of their own ends and their own politics.

I come from Mysore. We have been urging for a long time about the economic backwardness of the State of Mysore. Here, I would like to give you the figures of Central assistance given to the Mysore State during the First, the Second and the Third Plans. The Central Assistance in crores of rupees to Mysore during the First Plan was—47.00; the Second Plan—67.00 and the Third Plan—149.56 and during 1966-67—36.3; 1967-68—36.00 and 1968-69—36.90. The same is the case with Kerala. The figures are: First Plan—24.00; Second Plan—38.00 and Third Plan—123.11 and during 1966-67—28.3; 1967-68—31.00 and 1968-69—30.40.

This is how the Central assistance during all these Plans has been given to the southern States. I would like to suggest that the Planning Commission should have a separate cell to identify backward regions in every State to have a uniform development. The Planning Commission is a big hoax. I would like to suggest to the Government to create a separate cell for identifying backward regions in all the States.

Now, I would like to come another important thing as to how the Mysore State has been neglected in the matter of irrigation facilities. Under the 1924 Agreement of sharing of waters of Cauvery basin, the water has not been utilised. It is being neglected. The Central Government is neglecting the State of Mysore. Even under the 1924 Agreement, we are entitled to 45 Cmts. of water from the Cauvery basin. Since 1961, the Central Government has not given technical clearance to Hemavati project and also to Kabini project which are under progress. (*Interruption.*) The construction of Kabini project is in our State. If they want, we can give water to Kerala. Since 1961, the Central Government has not given clearance. Why ? What is the politics behind it ? The Central Government is playing politics between States and States. I would like to know whether the Government of India will give clearance and see that all the projects which are in the Cauvery basin are implemented and all the waters are utilised. Madras has no right even to claim water under the 1924 Agreement. The Central Government has given clearance to the construction of Bhawani project so far as Madras is concerned. Such a discriminatory treatment is being meted out by the Central Government to the State of Mysore.

I would like to have a categorical assurance from the Minister as to when the clearance is going to be given to the Hemavati project, the Kabini project and other projects in the Cauvery basin which are under progress. I want a categorical assurance from the Minister here and now.

श्री शिवचंद्रिका प्रसाद (जमशेदपुर) : सभापति महोदय, अभी जो चर्चा सदन में चल रही है, उसका मैं स्वागत करता हूं । देश में बहुत से ऐसे क्षेत्र हैं जो आर्थिक दृष्टि से पिछड़े हुए हैं मैं भी एक ऐसे ही प्रांत और क्षेत्र से आता हूं । बिहार की नेशनल इंकम पर-कैपिटा आज सारे भारत में लोएस्ट है—यह 2.99 है। बिहार प्रदेश में छोटा—नागपुर और संथाल परगना और भी पिछड़ा है। ढाल भूम सबडिवीजन, जिस क्षेत्र से मैं आता हूं, वह तो एकदम गया-गुजरा है । मैं यह मानता हूं कि छोटा नागपुर में कई एक बड़े कारखाने और खदान हैं, पर ये कारखाने अधिकतर रोजी-रोटी बिहार से बाहर के लोगों और क्षेत्र से दूर के लोगों को देते हैं ।

मैं चाहता हूं कि ऐसे क्षेत्रों में खेती के लिए उचित सिंचाई का प्रबन्ध होना चाहिए । अच्छी सड़कों का निर्माण होना चाहिए। गांव गांव में विद्युत पहुंचाने की व्यवस्था होनी चाहिए और लघु उद्योगों को प्रोत्साहन देना चाहिये ।

मेरे क्षेत्र में यानि दालभूम सब डिवीजन में अच्छी सड़कों के निर्माण के लिए, लिफ्ट इरीगेशन के लिए, बाढ़ागोड़ा ब्लाक, चकुलिया ब्लाक पदम्बदा ब्लाक, घाटशिला ब्लाक और पोरका ब्लाक के गांव-गांव में विद्युत पहुंचाने का यत्न जल्द से जल्द कराने के लिए और लघु उद्योगों को प्रोत्साहन देने के लिए, मैं आज चार वर्षों से सम्बन्धित अफसरों से विचार विमर्श और भारत सरकार और बिहार सरकार से लिखा-पढ़ी कर रहा हूं परन्तु दुर्भाग्य है कि सरकार ने अभीतक इस दशा में कोई कदम नहीं उठाया है । मैं चाहता हूं कि इस क्षेत्र में लोगों की आर्थिक स्थिति सुधारने के लिए जल्द से जल्द सही कदम सरकार को उठाने चाहिए ।

अगर वर्तमान पंचवर्षीय योजना में इसको पूरा करने के लिए कुछ अधिक पैसा खर्च करना पड़ तो वह भी कराना चाहिए । ऐसा करने से अभी जो बार-बार सुखाड़ इस क्षेत्र में होता है और जो बेरोजगारी बढ़ रही है उसमें अवश्य सुधार होगा ।

अच्छा हो यदि छोटा नागपुर के लिए और संथाल परगना के लिए जल्द से जल्द अलग-अलग डेवलपमेन्ट बोर्डों का गठन किया जाये ।

श्री अवैद्यनाथ (गोरखपुर) : सभापति महोदय, मैं आपका आभारी हूं कि आपने मुझे भी थोड़ा सा समय बोलने के लिए दिया है ।

[श्री अवधेशनाथ]

मैं गोरखपुर से चुन करके यहां पर आया हूं। 14 पूर्वी जिलों के पिछड़ेपन की स्थिति के सम्बन्ध में मैं भी कुछ निवेदन करना चाहता हूं। मैं आकड़ों की गहराई में नहीं जाना चाहता हूं। मैं आपको यह बताना चाहता हूं कि इस देश में तीन पंचवर्षीय योजनाएँ समाप्त हो गई हैं लेकिन आज भी उन पूर्वी 14 जिलों की जो हालत हम देखते हैं और दूसरी तरफ दिल्ली और लखनऊ की हालत देखकर उनकी तुलना करते हैं तो हम यही पाते हैं कि आज भी वे उसी स्थिति में हैं जिस स्थिति में वे 23 वर्ष पूर्व थे। यदि हम चाहते हैं कि पूर्वी जिलों की तरक्की हो, पूर्वी जिलों का जो पिछड़ापन है वह समाप्त हो तो उसका केवल एक ही उपाय है। आज भी उन जिलों की 85 फीसदी जनसंख्या खेती पर निर्भर करती है और वह खेती भी लाभकारी नहीं है। यदि हम चाहते है कि उन पूर्वी जिलों का सुधार हो तो उसका एक ही उपाय हैं कि वहां की सारी जनसंख्या को दूसरी दिशा में डाइवर्ट किया जाये और इसके लिये उद्योग-धंधों की आवश्यकता होगी। हमने बार-बार विधान सभा के अन्दर और संसद के अन्दर इस बात की आवाज उठाई है कि पूर्वी जिलों कि स्थिति सुधारने की तरफ प्लानिंग कमीशन ध्यान दे लेकिन प्लानिंग कमीशन ने प्रान्तों को जो रुपया दिया है वह जनसंख्या के आधार पर नहीं दिया है। यही कारण है कि आज भी हम गरीबी को उसी प्रकार से झेल रहे है। इसलिए मेरा निवेदन है कि यदि आप उन जिलों की आर्थिक दृष्टि से उन्नति करना चाहते हैं शिक्षा की दृष्टि से उन्नति करना चाहते हैं, तो उसके लिए वहां पर औद्योगिक वातावरण बनाना होगा। औद्योगिकरण के लिए आज लोग मांग करते हैं कि एक जिले में एक फैक्टरी हो जाये लेकिन इससे भी गरीबी दूर नहीं होगी। गरीबी दूर करने के लिए आवश्यक है कि वहां पर सड़कें बनाई जायें, बिजली सस्ती दी जाये। आज एक तरफ हम सुनते हैं कि हरियाणा के गांव गांव में बिजली पहुंच गई है लेकिन दूसरी तरफ हम देखते है कि उत्तर प्रदेश के पूर्वी जिलों में अभी केवल कुछ गांवों में ही बिजली गई है। ऐसी अवस्था से हम बड़े निराश है। इसी लिए आज उन 14 पूर्वी जिलों से यह आवाज उठ रही है कि यदि सरकार ने हमारी गरीबी की तरफ ध्यान नहीं दिया तो हम अलग सूबे की मांग करेंगे और यह मांग बराबर उठती जा रही है। यदि सरकार इस संकट से बचना चाहती है तो उसका एक ही उपाय है कि वह वहां पर औद्योगिक वातावरण बनाये, नयी सड़कें बनाये और शिक्षा की व्यवस्था करे। इसके साथ ही वहां पर बिजली सस्ती दी जाये। आज वहां पर जो बिजली दी जाती है उसमें पांच सौ रुपया फी कनेक्शन ले लिया जाता हैं जबकि दूसरे प्रान्तों में बिजली मुफ्त दी जाती है। इस सम्बन्ध में हमने केन्द्रीय बिजली मन्त्री के सामने मांग रखी हैं कि यह पांच सौ रुपया माफ किया जाये और उन्होंने अश्वासन भी दिया है कि उस को माफ किया जायेगा।

इस तरीके से वहां पर जो मिनिमम चार्ज किया गया है बिजली के लिए वह 10 रुपये पर हौर्स पावर है। वहां पर बिजली बराबर मिलती नहीं है। इस तरीके से वह एक प्रकार से उन को दंड ही देना पड़ता है। इसलिए मैं आप से यह अनुरोध करूंगा कि यदि आप पूर्वी जिलों की आर्थिक स्थिति को सुधारना चाहते हैं, वहां शिक्षा का प्रसार करना चाहते हैं, वहां की गरीबी को समाप्त करना चाहते है तो आप उस पिछड़े क्षेत्र में औद्योगिक वातावरण का निर्माण करें।

19.00 hrs.

आज ही मैंने सुना है कि वहां पर एक बहुत बड़ा थर्मल पावर स्टेशन बनाने की योजना थी लेकिन उस थर्मल पावर स्टेशन की योजना को कैंसिल कर देना पड़ा क्योंकि वहां पर बड़ी लाइन नहीं है। वहां पर बड़ी लाइन के लिए 90 टन की टरबाइन मशीन को ले जाने के लिए वैगन नहीं था और चूंकि पर्याप्त लोड लेने के लिए छोटी लाइन में डिब्बे नहीं है इसलिए वह योजना उनको स्थगित कर देनी पड़ी है।

यदि उस ऐरिया को डेवलप करना है तो जाहिर है कि वह एरिया तभी डेवलप हो सकता है जब खेती पर जो भार है उसको आप इंडस्ट्रीज लगा कर उधर बाँट दें । इंडस्ट्रीज तभी वहां पर बढ़ेंगी जब वहां पर आप सड़कें बनायेंगे । बड़ी लाइंस वहां पर जायेंगीं, बिजली वहां सस्ती होगी । इसलिए मैं अनुरोध करूंगा कि यदि आप चाहते हैं कि उस क्षेत्र से एक अलग सूबे की मांग न हो और यदि आप चाहते हैं कि वहां के लोग भी अच्छे सुन्दर तंदरुस्त दिख सकें जैसे कि देश के दूसरे भागों के लोग दिखाई देते हैं, जैसे की हम दिल्ली में देखते हैं, लखनऊ में देखते हैं और इधर मेरठ को देखते हैं, उत्तर प्रदेश के पश्चिमी जिलों को देखते हैं तो हमें मालूम होता है कि उधर हम लोग नर्क में हैं । इसलिए मैं अनुरोध करूंगा कि आप उस क्षेत्र की तरक्की के लिए औद्योगिक वातावरण बनायें उधर इंडस्ट्रीज सैट अप करने के लिए इंडस्ट्रियलिस्ट्स आकर्षित हों । जब तक वहां पर सड़कें नहीं होगीं, बड़ी लाइन नहीं जायगी और वहां शिक्षा का प्रसार नहीं होगा, जब तक स्माल स्केल इंडस्ट्रीज को डेवलप नहीं किया जायेगा तब तक वहां की गरीबी समाप्त नहीं हो सकती है । इन शब्दों के साथ मैं सभापति महोदय को धन्यवाद देता हूं कि उन्होंने मुझे समय दिया ।

SHRI A. SREEDHARAN (Badagara) : The wrong economic policies of this Government during the last 23 years have resulted in two economic evils: One, in concentration of wealth in the hands of individuals and business houses and second concentration of development and resources in certain areas of our country.

It is this contradiction which has defeated the three five-year plans, which has caused mounting unemployment in this country, which unfortunately is leading this country into an explosive situation.

The case of Uttar Pradesh has been very effectively argued here particularly by my colleague Mr. Sheo Narain. U.P's backwardness, as Mr. Umanath put it, is a writing on the wall. It is a signpost at the cross-roads of history.

I come from a State, the State of Kerala, where not only certain areas only, but the entire State is backward and underdeveloped.

The *per capita* income of Kerala is at the bottom of the list....

AN HON. MEMBER : Better than Bihar.

SHRI A SREEDHARAN : We have been shouting; you have not been shouting. I say this because Uttar Pradesh has 89 Members here, What were you doing? If the M. Ps. of Uttar Pradesh decide they can just throw out this Government. We are only 19 Members; that is our misfortune. Kerala has the highest density of population in this country, 1500 per square mile, perhaps the second highest in the whole world. Kerala earns 15 per cent of the total foreign exchange earnings of this country. And still, what is it that the Central Government has done in Kerala? What has been done to set up industries in Kerala during the last three five-year plans? During the entire three plan periods, this was only one per cent of the total investment in the entire Central industrial sector, whereas our population is 3.85 per cent. Whenever we talk of planning, we formulate a certain basis. But what is the basis on which Government have planned? Is population the basis? Are economic resources the basis? Is backwardness the basis? Are technical possibilities and potentialities the basis?

SHRI RANJEET SINGH : Power is the basis; political power is the basis.

SHRI A SREEDHARAN : What actually is the basis? Yes, power is the basis. During the last mid-term poll, when the Prime Minister toured Kerala, she said 'I am going to change the face of Kerala; I am going to face this challenge.' But I would like to ask what she has done. What about the development of electric power in our State? What about the sad and tragic story of the Cochin shipyard? Eight times, the foundation-stone of the shipyard was laid. Then, we had to fight in this Parliament persistently and consistently to open the eyes of this Government. But today what is happening in the Cochin

[Shri A. Sreedharam]

shipyard? We have the highest density of educated unemployed people in this country. We produce the largest number of unemployed people. You may go to any State, and you will see the people from our State working as hotel-walls, or as workers or as chowkidars in every State; You will find people from our State working everywhere. Now, they are being pushed out of Maharashtra, and they are asked to go back home. Where will they go back?

What is happening in the Cochin shipyard? Recruitment is going on. We pleaded with Government that here was a State where there was the highest density of unemployed people, and, therefore, let them not recruit people from outside. But people from outside are being recruited, in a State where unemployment is creating Naxalites, in a State where voilenee is becoming the order of the day, as the days pass by.

Again, what about the precision instruments factory at Puducherry? Government said that they were going to locate it there. But where is that factory now?

Again, what about the petro-chemical industry in our State? The Cochin Refineries is producing a surplus of naphtha; that can be utilised if a petro-chemical unit is developed there.

Then, there is the question of economic resources. It has been found that in my constituency there are huge deposits of iron ore. This iron ore should be developed. We have been pleading with the Central Government that we should be allotted a steel mill. Every other South Indian State has been allotted a steel mill; every other South Indian State has been given steel mills on the basis of other considerations. But the Kerala State has been let down badly. I pinpoint the case of Kerala not because I feel that Kerala alone is the backward area—I know that there are other backward areas in India also-but because these backward areas are going to create explosive situations in this country. If you have violence in this country, if the youth of this country have taken to the undemocratic path, if there are murders in this country, it is because of the wrong economic policies, it is because of the backward economic policies, it is because of the concentration of wealth in certain hands and concentration of wealth and resources and development in certain areas. This conflict is a volcano, and I would like to tell Government that they are sitting on the top of the volcano. Let them see the writing on the wall, and let them act now, for otherwise they will be demolished.

MR. CHAIRMAN : Now, Shri R.S. Arumugam.

SHRI TULSHIDAS JADHAV *rose—*

MR. CHAIRMAN : I am guided by the list distributed by the Whips and not by the individual chits. Now, Shri R.S. Arumugam.

* Shri R. S. ARUMUGAM (Tenkasi): Mr. Chairman. Sir, the National Development Council constituted two working groups to go into the question of backward regions of the country. One working group was headed by Shri Pande and the other one by Shri Wanchoo. the Working Group presided over by Shri Pande formulated certain norms for identifying the backward regions in the country. In accordance with those norms, 19 taluks were selected as backward areas in Tamil Nadu and among these 19 taluks 11 taluks were in Tirunelveli and Ramanathapuram districts of Tamil Nadu. Shri Umanath referred to the backward areas in Tiruchirappalli district.

No entrepreneurs have come forward to start industries in these backward areas. The Working Group under the chairmanship of Shri Wanchoo had made certain suggestions about the fiscal and financial incentives to be offered to the prospective entrepreneurs to encourage them to set up industries in these backward areas. The Working Group had suggested that in the matter

* The original speech was delivered in Tamil.

of issuing import licences to such entrepreneurs,the Central Government should be very liberal and that in the initial stages, for a period of 5 years, the industrialists should be exempted from income tax, Corporate Tax, Exise Duty and also import duty. The Group had also recommended that these people should be offered Development Rebate, Transport Subsidy and such other concessions. I don't think that this Government have so far implemented any of those recommendations, the result is that there has been no significant industrial development in these areas.

I would also like to say that the Director General of Technical Development should undertake comprehensive surveys of these areas and then bring out a publication specifying the type of industries which can be set up profitably in these areas. I am sure that such a pamphlet would be of immense help to the industrialists.

Mr. Chairman, Sir, these areas are not only backward in the matter of industries but also equally backward in agriculture. The Government of India are implementing the Intensive Agricultural Development Programme in selected districts in each State. I would suggest that if a similar scheme is formulated for these backward areas they would make agricultural progress.

In my district Tirunelveli, Shankarankoil, Alangulam, Manur and Koilpatti areas are chronically drought-affected areas. In this area, the people depend upon rain-fed tanks for irrigation. Even during the British rule, it was considered feasible to have dams on Keeriaru and Pambaiaru rivers. The people of this area have also been demanding for generations that dams should be constructed. If they are constructed, I am sure that this area would become fertile and self-sufficient in food grains.

Finally, I would say that East Ramanathapuram region is traditionally a dry area. For years and years Sethu Samudram project for the development of this area is being talked about. If this project is taken up for implementation in right earnest, it will not only benefit this region but also the whole country. The navigational routes for the ships which are now very circuitous will become shorter; employment avenues will be opened for the unemployed youths of the area. Instead of indulging in pious platitudes, the Government should energetically and earnestly implement such schemes for the development of these backward areas. With these few words, I conclude within the short time given to me.

श्री तुलसीदास जाधव : पहला मेरा अनुरोध यह है कि देश के अन्दर जो बैक्वर्ड एरियाज हैं उनको सबसे पहले एक लिस्ट बनाई जाए । लिस्ट बनाने के बाद प्लानिंग अप करें और प्रान्तिय सरकार को आर्डर दें कि उन इलाकों को प्रायोरिटी दी जाए और सैंट्रल गवर्नमेंट भी उनके लिए पैसा दे ।

दूसरा मेरा सुझाव यह है कि जो मकान रहीत लोग हैं तथा भूमिरहित जो लोग हैं, उनको बैंकों से पैसा दिलाने का इंतजाम किया जाए। गारंटी उनके पास न होने के कारण उनको पैसा नहीं मिलता है । इस वास्ते ऐसे लोगों की गारंटी या तो स्टेट गवर्नमेंट दे या कारपोरेशन दे और उनको पैसा बैंकों से दिलाया जाए ।

बैक्वर्ड एरियाज में छोटे छोटे उद्योग धंधे चालू किए जाएं । साथ ही जो इन उद्योगों को वहां लगाना चाहते हैं उनको सरकार फैसिलिटीज दे ।

जिन बैक्वर्ड एरियाज में बिजली है वहां बिजली का रेट कम किया जाए ताकि उद्योगों को तथा कृषि को प्रोत्साहन मिल सके ।

जो लोग वहां धंधे निकालें उनके लिए बिजली और पानी की सहूलियतें सरकार उपलब्ध करे। ऐसा अगर किया जाएगा तो बहुत से उद्योग धंधे वहां निकल सकेंगे और लोगों को काम मिल सकेगा और वे क्षेत्र आगे बढ़ सकेंगे ।

मेरी कांस्टिट्यूएंसी में भी ऐसे एरियाज हैं । शरुर ताल्लुका, इंदापुर, दौंड, करमाला आकोला

[श्री तुलसीदास जाधव]

और शोलापुर डिस्ट्रिक्ट । इनके लिए प्रायोरिटी देनी चाहिये ।

हर प्रान्त में जितने मिनिस्टर हैं, जो लोग सत्ता पर हैं वे अपने निर्वाचन क्षेत्र के लिए विभागों से सब कुछ करा लेते हैं, इस प्रकार की टीका होती है । लेकिन हमारी जो प्राइम मिनिस्टर हैं, उन्होंने अपनी कांस्टिट्युएंसी के लिए ऐसा कुछ नहीं किया है । प्राइम मिनिस्टर ने आम तौर से सभी को एक सरीखा समझा है और देखा है ।

श्री रणधीर सिंह : प्लानिंग का जो नजरिया है उनको आप बदलें । आप बड़े बड़े अंडरटेकिंग्ज प्लान करते हैं । इसको आप बन्द करें । जो हो चुके वे हो चुके आगे आप बन्द करें । सारा ध्यान जो है वह देहातों की तरफ आपको अब देना चाहिये बजाय इसके कि शहरों की तरफ दें । देहातों में दो चीजों का आप पहले इंतजाम कर दें । एक तो पानी दें ताकि पैदावार बढ़े और दूसरे बिजली दीजिये । पानी आप देंगे तो पैदावार बढ़ेगी और पैदावार बढ़ेगी और चीजें सस्ती होंगी और वहाँ जो गरीबी है वह मिटेगी लोगों को एम्प्लायमेंट मिलेगा । अगर आपने वहां बिजली दी तो जो वीकर सैक्शंज हैं, हरिजन हैं, बैक्वर्ड सैक्शंज हैं उनको बैंकों से पैसा मिलेगा और वे छोटे-छोटे उद्योग धंधे चला सकेंगे । इससे बेरोजगारी की जो वहाँ समस्या है वह भी हल होगी । अगर इन दोनों के साथ-साथ आपने गांवों को सड़कों से जोड़ दिया तो सारे देश में रेवोल्यूशन आ जाएगा । आज आप हजारों करोड़ रुपया बड़े-बड़े अंडरटेकिंग्ज में डाल देते हैं और वे घाटे में चलते हैं । जिन को आप ने चला दिया उनको तो आप चलने दें, लेकिन आगे के लिए आप स्थिति को साफ करें । हर तरफ से मांग आ रही है कि स्टील प्लांट दो अब अगर स्टील प्लांट लगा दिये जाते हैं तो उससे एम्प्लायमेंट नहीं मिलता है । हम ने देखा है कि बिहार और दूसरे सूबों में इन बड़े-बड़े प्लांट्स को लगाने से वहां का पिछड़ापन दूर नहीं हुआ है, लोगों की तरक्की नहीं हुई है । इसलिये बड़े बड़े प्लांट्स लगाने के बजाये वह रुपया बिजली, सड़कों और पानी पर लगाया जाये । पानी के लिए बड़े-बड़े डैम्ज और ट्यूबवैल्ज का इन्तजाम किया जाये । हरियाणा, पंजाब, यू० पी० और बिहार के नीचे पानी की बहुत बड़ी झील है, गंगा के बेसिन का पानी भरा पड़ा है । उस नीचे के पानी को निकाला जाये और उसके लिए ट्यूबवैल्ज लगाये जायें । बजाये इस के कि हमारे पढ़े लिखे लड़के बाबू बनें, उन को देहात में भेजा जाये । उन को दो, चार, पांच हजार रुपये का कर्जा दिया जाये ताकि वे देहात में छोटी-छोटी फैक्टरीज लगायें और अपने हाथ से खेती करें । इस से देश की काया-पलट हो जायेगी । मैं सिर्फ हरियाणा की बात नहीं करता हूं । यह सारे देश के लिए जरूरी है । यह जरूरी है कि सरकार अपने प्लानिंग में देहात की तरफ जाने, गो टु दि विल्लेजिज, का नजरिया अपनाये । देश भर में एग्रो-इंडस्ट्रीज का जाल बिछा दिया जाये । देहात में जो करोड़ों लोग रहते है, अगर उनको उठा दिया जायेगा, तो सारा देश उठ जायेगा । क्या सरकार प्लानिंग में यह शिफ्ट लाने के लिए तैयार है या नहीं ?

THE MINISTER OF STATE (SHRIMATI NANDINI SATPATHY) : I share fully the concern expressed by the hon. Members here that even after nearly two decades of planning, certain regions and districts and States of this country remain comparatively backward. I also come from a State which is generally recognised as a backward State, and I know the feeling of the people there.

Here, mainly the eastern districts of U. P. were discussed. It is true that the eastern districts of U. P., and not only these districts but as I have already said, many parts of the country, many States, are still remaining very, very backward. At the same time, I would like to mention here that the Planning Commission as well as the Central Government are fully aware of the situation, and from the beginning it has always been the concern of the Planning Commission and the Central Government to see that the regionel imbalances are

removed. For that certain steps have been taken during these years.

One of the hon. Members mentioned about the Patel Committee which was appointed some years back for the eastern districts of U. P. I may recall that it was the late Prime Minister Pandit Jawaharlal Nehru who had specifically invited the attention of the Planning Commission in the early 'sixties' to the conditions prevailing in these eastern districts. It was on his initiative that the Planning Commission constituted a special team under Shri B.C. Patel to tour these districts and to find out what special measures should be taken in these districts. This Committee not only reported about the special measures that have to be taken in the eastern districts of U.P., but also pointed out that certain special measures should be taken regarding the backward areas of the country.

As far as the recommendations of the Patel Committee are concerned, I should like to mention here that four eastern districts of U. P., Gazipur, Azamgarh, Deoria and Juanpur, were visited by the Committee. The report suggested an additional outlay of Rs. 10-49 crores for the last three years of the Third Plan, and an outlay, as was mentioned by the hon. Member, of Rs. 74·6 crores for the original Fourth Plan period.

The main responsibility for the implementation of these recommendations would really be that of the State. However, in order to assist the State in its efforts to step up the pace of development in these four districts, additionalassistance of Rs. 4 crores was given in 1964-65 and Rs. 4·5 crores in 1965-66. Two other districts, Balia and Basti were also included in the programme of special development Later on, as hon. Member are aware due to aggression and certain developments in the country, it could not be followed up.

At this stage I shall only mention generally about the steps that are taken by the Government to remove regional imbalances and disparities. My hon. friend Shri Umanath said something which was not correct. In 1962 the Planning Commission had to finalise the criteria. Fifteen indicators were finalised; that was about distribution of central assistance to different States. This committee, the Pandey Committee,the Wanchoo Committee and two other committees set up later on were to find out the industrially backward regions. These are two separate things. This Committee which was set up, as was stated by the then Planning Minister, was to give certain indicators to decide on distribution of central assistance; it is something different from the indentification of the backward areas.

SHRI UMANATH : No, it is not for distribution but for identification.

SHRIMATI NANDINI SATPATHY : There were certain criteria under which central assistance was distributed to different States. One of those criteria was that ten percent of the total central assistance should be given to those States which were backward, U. P. comes under that category and it got a share out of 10 percent. Similarly, one of the fifteen indicators was that sixty percent of the total assistance should be distributed on a Population basis. U.P., Bihar and some other states came under that criterian also. Our Plans recognise that imbalances exist and that action is called for the correction of those imbalances. But we should remember that such imbalances exist not only between different States but also between different areas within a State. Even in the so called advanced States there are backward pockets and some hon. Members who come from comparatively forward States have expressed their concern over this. The correction of these imbalances is necessarily a longterm process and we have made a beginning....(*Interruptions*) I should like to say that it is a very determined beginning and comparatively backward States have been given weightage in the allocation of central assistance.Ten percent of the central assistance in the Fourth Plan has been reserved to be distributed exclusively among the backward States—U.P., Bihar, Orissa, M.P., Rajasthan and Kerala.

SHRI SHEO NARAIN : What about the Patel Commission recommendations ?

SHRIMATI NANDINI SATPATHY : After that, there were certain others also.

SHRI K. LAKKAPPA : Mysore also has backward areas. Why this discrimination ?The States have been asked to identify their backward areas and incorporate schemes for their accelerated development. Most of the states have completed this process of identification of backward districts. Uttar Pradesh has identified 27 districts as backward, including the districts of Eastern Uttar Pradesh. The Planning Commission has refrained from determining on its own the backward regions but certain criteria have been suggested to the State Governments, and they have identified their backward areas on the basis of these or other criteria that they might like to evolve. The States are also being passed to prepare district plans for the conservation and development of resources and creation of the infrastucture such as communication, marketing, etc., esepecially in the light of the requirements of the backward people. The Planning Commission proposes to keep a watch over the progress of development in these areas so as to bring them up to the level of the other areas within the state. The Planning Commission has also set up a separate working group to discuss the problem of backward areas in connection with the formulation of the annual plans of the States for 1971-72.

I would like to invite the attention of the hon. Members to the fact that the fourth Plan incorporates a number of special programmes for the benefit of weaker sections of our people.Out of these special programmes, there is the programme for the development of dry and arid areas which are among the most backward regions in the country. An outlay of Rs. 100 crores will be made available during the fourth Plan period for an integrated progamme of rural works.

I would like to mention here that some of the districts of Uttar Pradesh come under such plan. Out of these, for small farmer projects, four districts; marginal farmers and agricultural labour projects, two, and dry farming project, two.

SHRI SHEO NARAIN : What are the names of those districts ?

SHRIMATI NANDINI SATPATHY ; I will give the names. The Plannig Commission and the Government are also aware that the pace of industrial development has beeh extremely uneven as between different parts of the country and that certain areas, for example, the eastern districts of Uttar Pradesh, have not felt the impact of industrialisation yet. That is why, as the House is aware, the Planning Commission set up two working groups about which we discussed here: they are commonly known as the Wanchoo Committee and the Pande Committee. One committee was set up to fix the criteria for the identification of backward regions and the other to find out and recommend certain fiscal and financial measures to give incentive to the industries which will go to those backward regions. After the receipt of the reports of these two groups, the National Development Council discussed them and then a certain formula was evolved. Under that, the States were asked to submit the list of their backward districts to the Planning Commission. Now, different States have submitted their lists of backward districts. I would like to inform hon. Members that from Uttar Pradesh, these are the districts: Almora, Azamgarh Bahraich, Banda, Ballia, Chamoli; Fatehpur, Garhwal, Deoria, Gorakhpur, Hardoi, Pilibhit, Jounpur, Jhansi, Pratapgarh, Pithoragarh, Sultanpur, Tehri Garhwal, Uttarkashi, and so forth. A number of districts are there.

SHRI SHEO NARAIN : Basti is not there. (*Interruption*) What is the Government doing ? it is among the poorest districts in the country.

SHRIMATI NANDINI SATPATHY ; I did not read the whole list. Basti is also included in the list. Then, Etawah, Faizabad, Gonda, Mirzapur—a number of districts. Basti is one of them. Also, these districts are selected for concessional financing from the financial institutions to set up industries there.

SHRI UMANATH : which are the districts in Tamil Nadu ?

SHRIMATI NANDINI SATPATHY : Let me finish with UP first.

श्री झारखंडे राय : मैं यह जानना चाहता हूं कि पटेल कमीशन की तरह से पूर्वांचल के इन 14 जिलों के लिए आप कोई कमीशन बन ने के लिए तैयार हैं या नहीं ?

SHRIMATI NANDINI SATPATHY ; Besides, so far as UP is concerned. Ballia Jhansi have been identified as the two industrially backward districts which would qualify for subsidy and investment.

Apart from this, the States have also identified districts for setting up industrial units with concessional finance which I have already said. UP has identified a large number of districts—27 out of 55. The concessions announced by the financial institutions, the Industrial Development, Bank of India and the Industrial Finance Corporation comprise a number of things like lower rate of interest, extension of initial moratorium for repayment of loan, etc. These are the concessions which will be given to the industries which go there.

SHRI RANJEET SINGH : Who will set up industry in areas with no roads, no water, etc. ?

SHRIMATI NANDINI SATPATHY : The State Government has a greater responsibility for providing road,electricity, etc.

SHRI RANJEET SINGH : They have asked for money which you do not give.

SHRIMATI NANDINI SATPATHY : UP got its share of central assistance. It is for every State Government to distribute the assistance given them among the different regions. It is their responsibility to see that their backward regions also develop.

श्री राजदेव सिंह : पिछली तीन पंचवर्षीय योजनाओं में यू.पी. को प्रपोर्शन के हिसाब से कम दिया गया है तो उसको आप किस तरह से कम्पेन्सेट करने जा रहे हैं?

SHRIMATI NANDINI SATPATHY : I do not think the hon.member is correct. UP is not given less. It is for the State Government to see that potential entrepreneurs go to the backward areas. It is for the State Government to see that vital industrial projects are formulated. They should ask for finance from these financial institutions.

An integrated programme for provision of requisite facilities such as power, water-supply, roads, etc., has also been drawn up and implemented as part of the State plan. Our past experience has shown that unless these infrastructural facilities are provided, no amount of State sponsorship of new industrial units would prove fruitful. So, it is for the State Governments to help in these matters and see that things develop as quickly as possible.

The rate of economic growth of any region or State is not determined solely or even primarily by central investment in industries, as we could see from the example of Bihar. With the largest central investment in industries, Bihar is still one of the poorest States, whereas States like Punjab and Haryana have come up very well.

The development of a large number of small-scale industries and agricultural productivity accounts for the relative prosperity of the different states.

During the discussion certain questions were raised by some hon. Members. One hon. Member said that the number of villages electrified in Uttar Pradesh is very small in comparison with other States. I should like to state that in 1961 the number of villages electrified in UP was 4,866 out of a total of 25,453 in the whole country. In 1969 the number has gone up to 12,310. It is true that all the villages in UP should be electrified like in Haryana. I agree with him there. But the outlay for rural electrification in the State plan of UP is Rs. 61 crores. 1,50,000 pump sets would be energised in this State.

SHRI SHAMBHU NATH : In this part or the whole of UP?

SHRIMATI NANDINI SATPATHY : In the whole of UP. the number of pumps up to the end of the Third Plan was only 17,591. In the coming years the pace of rural electrification will be considerably stepped up.

[Shrimati Nandini Satpathy]

Shri Shambhu Nath and some other hon. Members suggested that there should be a separate board for the development of eastern UP. This is a matter primarily for the State Government to consider. So far as the Central government are concerned, we have been urging the State Government to draw up integrated district wise plans. When such plans are drawn up the problems of development of eastern UP and other backward regions would receive due attention.

The hon. Member, Shri Tiwary, referred to backward areas of Bihar. Unfortunately, he is not present here. I would like to state that four districts have been identified as backward districts in Bihar, and they are Saharsa, Dharbhanga, Champaran and Muzaffarpur. All these are districts which are entitled to concessional finance. So far as Dharbanga is concerned, it is entitled to a capital subsidy of 10 per cent for new industrial units. Champaran has been selected for a small-scale small farmers' development programme also.

Here I would like to mention that we are all very much concerned about the development of the backward regions. At the same time, I would like to state that the amount of Central assistance which was to be given to the different States has already been distributed. This assistance was distributed on certain broad criteria. So, there is no question of showing different attitudes toward different states, what is called, *sautela bhaivyavahar*. I would like to state that there was no such attitude towards any State whatsoever, because the entire Central assistance was distributed on certain broad criteria.

At the end, I would like to mention that while talking about the backwardness of UP, some hon. Members referred to some other backward areas.

SHRI UMANATH : What about Tamil Nadu? You said, after UP you will come down to Tamil Nadu.

SHRIMATI NANDINI SATPATHY : I am sorry. The districts from Tamil Nadu have not yet been finalised by the Planning Commission. As soon as it is finalised, it will be given to the hon. Member.

SHRI RANDHIR SINGH : What about Haryana?

SHRIMATI NANDINI SATPATHY : In Haryana, Mohindergarh and Hissar are the districts in the list.

SHRI A. SREEDHARAN : Please give the names of districts from Mysore and Kerala also.

SHRIMATI NANDINI SATPATHY : About Kerala the proposals are still under consideration and about Mysore the districts are Chitradurga, Raichur, Bellary, Bijapur and Bidar.

SHRI K. LAKKAPPA : Mysore State is the most backward State. Why have so many other districts been left out? Why is discriminatory treatment being meted out to Mysore?

MR. CHAIRMAN : Order, order. It is not for her to include those districts.

SHRIMATI NANDINI SATPATHY : As I have already said, it is the concern of the Central Government as well as the Planning Commission to see that backward districts and regions of this country are developed as quickly as possible. It is equally the responsibility of the State Governments to see that their backward regions are properly identified and they should allocate a good amount for the development of their backward regions.

In this connection, while mentioning about the backward regions and the poverty of the people some of the Members

brought in certain politics here..... (*Interruption*). I would like to remind hon. Members that it is not only the responsibility of the Central Government but, as I have said, it is equally the responsibility of the State Governments as well as of hon. Members who are in the Opposition. If they really sincerely and seriously want to improve the lot of their people, they should cooperate and try to see that we develop all backward regions of the country..... (*Interruption*). No politics and personal insinuations should be brought into these things.

19.43 hrs.

The Lok Sabha then adjourned till Eleven of the Clock on Friday, December 4, 1970/ Agrahayana 13, 1892 (Saka).

NAI DUNIA PRESS INDORE—1010-1-71